RNI No.DELHIN/2011/41355

दिल्ली से प्रकाशित

सितंबर 2025 वर्ष 14 अंक 166 मूल्य 20

प्राइम स्पेक्टेटर

राजनीति पीएसयू और अपराध पर केंद्रित पत्रिका

शंघाई से क्या निकलेगा?

PRIME INDIA MEDIA HOUSE →

PRIME CRIME INDIA

www.primecrimeindia.com

PSU TODAY

NETA INDIA

www.netaindia.com

LONDON DAIRY
Premium Ice Cream
SHEER INDULGENCE
LONDON DAIRY
Premium Ice Cream
DOUBLE CHOCOLATE
LONDON DAIRY
Premium Ice Cream
NEW FIG WALNUT
LONDON DAIRY
Ice Cream with Yoghurt
mango
londondairy.in
londondairyindia
londondairy.com

संपादकीय

नासिर खान
संपादक

पंजाब बाढ़ की विभीषिका

उत्तर से दक्षिण भारत तक जब भी कोई आपदा या संकट देश पर आया है, पंजाबियों ने आगे बढ़–चढ़कर पीड़ितों की मदद की है। पंजाब की धरा से गुरुओं व पीर–पैगम्बरों ने मानवता के उत्थान व मिल–जुलकर खाने की सीख दी है। गुरुओं का यह संदेश देश–दुनिया में प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है। ऐसे वक्त में जब पंजाब बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है तो शेष देश के लोगों को निस्वार्थ भाव से आगे आने की जरूरत है। उल्लेख करना जरूरी है कि पंजाब के लोग हमेशा बेहद स्वाभिमानी रहे हैं। इस सीमावर्ती राज्य ने गाहे–बगाहे विभिन्न चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया है। मध्यकाल में विदेशी आक्रांता रहे हों या आजादी के बाद पाकिस्तान के आक्रमण, पंजाबियों ने भारत की सुरक्षा ढाल बनकर जीवटता का परिचय दिया है। यहां जरूरी है कि किसी मदद से पहले पंजाबियों के स्वाभिमान का विशेष ख्याल रखा जाए। यूं तो इस आपदा की घड़ी में सेना के अलावा पंजाब के विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठन अपने स्तर पर लोगों को संकट से उबारने के काम में प्राणपण से लगे भी हुए हैं। लेकिन आपदा का बड़ा स्तर देखते हुए शेष देश से योगदान की उम्मीद की जा रही है। निस्संदेह, आपदा का दायरा बड़ा है, जिसमें राज्य के 23 जिलों में करीब तीन लाख से अधिक लोग जलप्लावन का त्रास झेल रहे हैं। बड़े पैमाने पर कृषि भूमि जलमग्न हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संकट की इस घड़ी ने लोगों को स्वतरूस्फूर्त रूप में एकजुट किया है। पंजाबियों का जज्बा देखिए कि सरकारी मदद पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने उफनते पानी में नावें उतार दीं। उन्होंने न केवल पड़ोसियों, बच्चों–बूढ़ों को बचाया, बल्कि पशुओं को बचाने के लिये भी भरसक प्रयास किए। सारी दुनिया में मानवता का पर्याय बने लंगर लगाए गए। जगह–जगह अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए। बिना किसी संकोच के राशन बांटा गया।

निस्संदेह, पंजाबियों की यह भावना कोई पहली बार नहीं देखी गई। अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी मदद के तमाम प्रेरणादायक उदाहरण हमारे सामने हैं। अब चाहे तुर्की का भूकंप हो या केरल में प्राकृतिक आपदा का तांडव, पहले प्रतिक्रिया देने वालों के रूप में पंजाबियों की विशिष्ट पहचान रही है। खालसा एड, यूनाइटेड सिख्स, हेमकुंट फाउंडेशन और अनगिनत स्थानीय गुरुद्वारों से जुड़े संगठनों ने मुश्किल वक्त में तेजी से काम किया है। जरूरतमंद लोगों तक भोजन,पानी,दवा और चारा पहुंचाया है। गुरुदासपुर और कपूरथला में स्वयंसेवकों ने कमर तक गहरे पानी में जाकर संकटग्रस्त लोगों को बाहर निकाला है। इतना ही नहीं, पशु चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में फंसे मवेशियों की देखभ: ाल कर रहे हैं। वित्तीय मदद भी मिल रही है, जिसे राज्य व केंद्र सरकार द्वारा अविलंब बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही गैर सरकारी संगठन, परोपकारी लोग और यहां तक कि कलाकार भी लोगों की मदद व पुनर्वास का संकल्प ले रहे हैं। एक पंजाबी सेलिब्रिटी ने 200 घरों के लिये सहायता का वायदा किया है। जो इस बात का प्रमाण है कि कैसे सांस्कृतिक हस्तियां तबाही की विभीषिका कम करने के लिये सामुदायिक समूहों के साथ आगे आ रही हैं। निस्संदेह, इस संकट की घड़ी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायु सेना ने नावों, हेलीकॉप्टरों और राहत शिविरों के जरिये पीड़ितों को तात्कालिक राहत पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। वे तसवीरें मानव सेवा के संकल्प को दर्शाती हैं, जिसमें ग्रामीणों ने ट्रैक्टर–ट्रालियों को जीवन रक्षक नौकाओं में तब्दील कर दिया है। प्रवासी समूहों द्वारा आर्थिक मदद भेजना भी एक सुखद पहल है। निस्संदेह, पंजाब में इस सेवा की संस्कृति और निस्वार्थ पहल की बार–बार परीक्षा भी हुई है।

शंघाई से क्या निकलेगा ?

6

प्राइम स्पेक्टेटर

संपूर्ण हिंदी मासिक पत्रिका

DAVP No.0813F27125-025

वर्ष-14, अंक:166, सितंबर 2025

मल्य ₹ 20

RNI No.DELHIIN/2011/41355

संपादक
नासिर खान

सलाहकार संपादक
राकेश त्रिपाठी

राजनीतिक सपादक
ए पी सिंह

संपादक (सूचना प्रौद्योगिकी)
प्रशांत दत्त मिश्रा

कानूनी सलाहकार
डी.बी.गोस्वामी,सलीम खान
(एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)

चीफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव
समीर अख्तर

विदेश प्रतिनिधि
विकास पारिक (लंदन)

प्रमुख प्रतिनिधि

दिल्ली ब्यूरो प्रमुख
सतपाल सिंह तंवर

लखनऊ ब्यूरो प्रमुख
अशोक तिवारी

मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख
श्वेतांक वर्मा

हरियाणा ब्यूरो प्रमुख
संजय सिन्हा

उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख
सुनील नेगी

पूर्वांचल ब्यूरो प्रमुख
शाहिद अस्करी

सोनभद्र ब्यूरो प्रमुख
संजय सिंह

बरेली मण्डल ब्यूरो प्रमुख
योगेंद्रपाल सिंह कौशल

बिहार ब्यूरो प्रमुख
शक्ति प्रकाश

महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख
राजकुमार केशरवानी

हिमाचल ब्यूरो प्रमुख
साहिल शर्मा

राजस्थान ब्यूरो प्रमुख
रानू पाठक

पशिचम बंगाल,दिल्ली एनसीआर ब्यूरो प्रभारी
नरेश कुमार श्रीवास्तव

चीन-रूस-भारत: नई धुरी की ताकतवर तिकड़ी 9

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 42

संपादकीय 3

नेपाल का 'जेन जी' आंदोलन 14

बिहार: सर की सियासत 18

कब सचेत होंगे 36

असहमति दबाने का हथियार 39

स्मृति इरानी के शो 42

हॉकी का स्वर्ण पदक 48

क्षेत्रीय प्रतिनिधि

दिल्ली ब्यूरो
मोहम्मद आसिफ (वरिष्ठ संवाददाता)

मथुरा ब्यूरो
विनय चौधरी (संवाददाता)

कानपुर ब्यूरो
अजय कुमार द्विवेदी (वरिष्ठ संवाददाता)

इलाहाबाद ब्यूरो
गुफरान खान (वरिष्ठ संवाददाता)

मीरजापुर ब्यूरो
संजीव कुमार जैन (वरिष्ठ संवाददाता)

बलिया ब्यूरो
डॉ.कलीम वारसी (वरिष्ठ संवाददाता),

आरा ब्यूरो
विमलेश कुमार (संवाददाता)

हाजीपुर ब्यूरो
राहुल कुमार (संवाददाता)

कार्यालय

कॉरपोरेट ऑफिस

91, फर्स्ट फ्लोर जे एंड के ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली– 110092

संपादकीय कार्यालय

आर–141/3 रमेश पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली–110092

मोबाइल–9718647540Ph.011-46536014

ईमेल–primespectator@gmail.com,primeindia-mediahouse@gmail.com

वेबसाइट–primeindiamediahouse.com

primecrimeindia.com & netaindia.com

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक एवं संपादक नासिर खान द्वारा ANEJA PRINTERS,C–11,SECTOR-10,NOIDA (UP)से मुद्रित तथा आर–141/3 रमेश पार्क,लक्ष्मी नगर,दिल्ली–110092 से प्रकाशित। सभी पदाधिकारी अवैतनिक हैं। प्राइम स्पेक्टेटर के किसी भी रचना के प्रकाशन से पहले संपादक की अनुमति अनिवार्य है। पत्रिका में प्रकाशित लेख,लेखक के निजी विचार हैं। सभी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

शंघाई से क्या निकलेगा ?

सितंबर महीने की शुरुआत में चीन के तियानजिन में आयोजित हुआ शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का शिखर सम्मेलन काफी सुर्खीयों में रहा था और उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था. दरअसल, भू–राजनीतिक उथल–पुथल के बीच वैश्विक दक्षिण के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में शामिल हुए थे और सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं ने अहम द्विपक्षीय बैठकें भी की थीं. साल 2015 से ही भारत और पाकिस्तान के एससीओ में शामिल होने पर चर्चाएं तेज हो गई थीं. तब से इस संगठन का विस्तार चर्चा का प्रमुख मुद्दा रहा है. एससीओ के गठन को एक दशक हो चुका है और इसमें आज कई देश शामिल हैं, साथ ही इसका दायरा भी काफी व्यापक हो गया है. जाहिर है कि एससीओ में भी कई मसले ऐसे हैं, जिन पर सदस्य देशों की राय एक नहीं है, नतीजतन उन मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं हो पाता है. खास तौर पर तीन बड़े ज्व. लंतशील मुद्दों यानी आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से निपटने पर सदस्य देश एकमत नहीं है और इस कारण इन मुद्दों पर निर्णायक फैसले लेने में रुकावटें आ रही हैं. वर्तम. ान में, भारत–चीन संबंधों में फिलहाल नरमी आई है और व्यापार विवाद की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव आ गया है. इन सारी वास्तविकताओं के बीच तियानजिन एससीओ समिट में सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और भू–राजनीतिक मामलों समेत कई समझौतों पर सहमति बनी है.

एससीओ का विस्तार

पिछले तीन वर्षों के दौरान एससीओ के सबसे प्रमुख एजेंडे में इसका विस्तार भी शामिल रहा है. ईरान साल 2023 में, जबकि बेलारूस वर्ष 2024 में एससीओ का सदस्य बना था. देखा जाए तो शंघाई सहयोग संगठन का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और 10 अन्य राष्ट्रों ने भी इसमें शामिल होने की इच्छा जता. ई है. हाल ही में तियानजिन में आयो. जित एससीओ समिट ने दिखाया कि इस संगठन की पहुंच कितनी व्यापक हो चुकी है. पश्चिम में मिस्र से लेकर दक्षिण पूर्व में कंबोडिया तक दुनिया के हर का. `ने में स्थित देश इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे. हालांकि, फिलहाल ज्यादातर देशों को एससीओ में डायलॉग पार्टनर यानी संवाद साझीदार का ही दर्जा मिला हुआ है. ये देश एससीओ में अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं. एससीओ में डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल होने वाला लाओस सबसे नया सदस्य राष्ट्र है.

एससीओ ने नए सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऐलान किया है कि वह ष्डायलॉग पार्टनरष् और ष्ऑब्जर्वरष् के दर्जे को एक नई श्रेणी ष्एससीओ साझीदारष् में विलय कर देगा. यानी एससीओ के दो पर्यवेक्षक देशा. ` (मंगोलिया और अफगानिस्तान) एवं 15 संवाद साझीदार राष्ट्रों समेत सभी एसस. ीओ प्लस देश (“ब्ब च्सने अर्थात संवाद व पर्यवेक्षक देश”) भविष्य में न केवल एससीओ समिट की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे, बल्कि कुछ सहयोगी पहलों में भी शामिल हो सकेंगे. हालांकि, इसमें एक बड़ी अड़चन यह है कि एससीओ साझीदार दर्जे वाले देश सिर्फ एससीओ सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश के आमंत्रण पर ही आयोजन में शामिल हो पाएंगे.

जाहिर है कि एससीओ में भी कई मसले ऐसे हैं, जिन पर सदस्य देशों की राय एक नहीं है, नतीजतन उन मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं हो पाता है. खास तौर पर तीन बड़े ज्वलंतशील मुद्दों यानी आतं. कवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से निप. टने पर सदस्य देश एकमत नहीं है और इस कारण इन मुद्दों पर निर्णायक फैसले लेने में रुकावटें आ रही हैं.

तियानजिन में आयोजित एससीओ प्लस की बैठक में साफ तौर पर देखने को मिला कि चीन और रूस इस संगठन की ताकत और पहुंच को पूरी दुनिया के सामने दिखाने के लिए कितने अधीर हैं. हालांकि, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि एससीओ के दूसरे सदस्य देश तियानजिन की तरह व्यापक स्तर पर कूटनीति के इस बड़े आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार होंगे या नहीं. इसके अलावा, यह भी हो सकता है कि वैश्विक दक्षिण के कई देश बिना किसी अतिरिक्त प्रतिबद्धता के ही एससी. ओ के साथ जुड़े रहने के लिए तैयार

हों. हालांकि, अगर कोई देश इस तरह का दृष्टिकोण रखता है, तो फिर उसके एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने में रुकावट आ सकती है और वो इस संगठन का स्थाई सदस्य बनने से वंचित रह सकता है. उदाहरण के तौर पर पिछले दो दशक से ज्यादा समय से एससीओ–आसियान वार्ता चल रही है, लेकिन इसका कोई खास नतीजा अब तक नहीं निकला है. यानी न तो इस वार्ता के चलते कोई अहम समझौता हुआ है और न ही कोई आपसी सहयोग स्थापित हो पाया है. जाहिर है कि कई आसियान सदस्य देश (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार) एससीओ प्लस का हिस्सा है, लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर संगठन का फोकस ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिहाज से कोई खास उत्साहजनक नहीं रहा है, बल्कि कहा जाए कि चिंताजनक ही रहा है. बता दें कि इन अधिकांश दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को प्रमुखता दी जाती है.

इसी तरह से एससीओ के सदस्य देशों के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी आम सहमति नहीं है और कहीं न कहीं विरोधाभासी नजरिया कायम है. अफगानिस्तान हालांकि, एससीओ की चर्चा में एक अहम एजेंडा है. एससीओ में विशेष एससीओ–अफगानिस्तान संपर्क समूह बनाए जाने से भी पता चलता है कि संगठन के लिए अफगानिस्तान का मुद्दा कितनी अहमियत रखता है. अफगानिस्तान औपचारिक तौर पर एससीओ प्लस का हिस्सा है. इतना सब होने के बावजूद एससीओ में इस पर कोई आम सहमति नहीं है कि अफगानिस्तान के तालिबान शासन के साथ किस तरह संपर्क स्थापित किया जाए. जाहिर है कि इन हालातों में अफगानिस्तान के लिए एससीओ की पूर्ण सदस्यता हासिल करना असंभव सा हो जाता है. इतना ही नहीं, एससीओ सम्मेलनों में तालिबान शासन के प्रतिनिधियों को बुलाया भी नहीं जाता है. इससे भी पता चलता है कि संगठन में अफगानिस्तान को लेकर सदस्य देशों का रुख अलग–अलग है. अफगानिस्तान के तालिबान शासन के नुमाइंदों को तियानजिन एससीओ समिट में भी आमंत्रित नहीं किया गया था.

एससीओ में सुरक्षा एजेंडे को किया गया किनारे

निसंदेह तौर पर एससीओ में भौगोलिक विस्तार पर खासा ध्यान दिया जा रहा है. लेकिन एक और अहम बात जो साफ दिखाई दे रही है, वो यह है कि संगठन ने सुरक्षा से जुड़े अपने एजेंडे से फोकस हटा दिया है और इसकी जगह पर आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सहयोग को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है. एससीओ में आए इस बदलाव के दो कारण हो सकते हैं.

सबसे पहला कारण तो यह हो सकता है कि विस्तारित शंघाई सहयोग संगठन में सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और भू–राजनीतिक मसलों पर आम सहमति नहीं बन पा रही और इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं. हालांकि, तियानजिन में हुई एससीओ बैठक के बाद जारी किया गया घोषणापत्र इसका अपवाद था. इस घोषणा पत्र में कूटनीतिक प्रयासों की सफलता झलकती है, यानी सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सदस्यों में एक राय नजर आती है. खास तौर पर इस घोषणापत्र में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के नजरिए से तालमेल बनाते हुए इसमें जहां पहलगाम आतंकी हमले का मसला शामिल किया गया, तो खुजदार और जाफर एक्सप्रेस पर हुए आतंकवादी हमलों का भी उल्लेख किया गया. इस घोषणापत्र में ईरान के खिलाफ इजराइली और अमेरिकी सैन्य हमलों की न सिर्फ निंदा की गई, बल्कि इन्हें आक्रामक कार्रवाई" भी बताया गया. इतना ही नहीं, इन हमलों को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन भी कहा गया. इसके बाद, जब इजराइल ने दोहा पर हमला किया था, तब भी एससीओ ने एक बयान जारी कर इस आक्रामक कार्रवाई को "अस्वीकार्य" बताया था. ईरान और दोहा के मामले में देखा जाए तो फिलहाल भारत एससीओ के नजरिए के साथ खड़ा है, जो दिखाता है कि जून 2025 के बाद से इस क्षेत्र को लेकर नई दिल्ली का कूटनीतिक दृष्टिकोण बदला है. जाहिर है कि तब 12 दिनों के इजराइल–ईरान युद्ध के दौरान इजराइली हवाई हमलों की कड़ी निंदा करने वाले एससीओ के वक्तव्य से भारत ने खुद को अलग कर लिया था. हालांकि, तियानजिन बैठक में एससीओ सदस्य देशों के बीच सभी मुद्दों पर विचार–विमर्श हुआ, बावजूद इसके कुछ सदस्य राष्ट्रों के बीच छाए गहरे मतभेदों का कोई हल इस समिट में नहीं निकाला जा सका.

एससीओ में रुख में आए इस बदलाव का दूसरा कारण वर्तमान में रूस की स्थिति में आया परिवर्तन है. इसके चलते एससीओ आर्थिक सेक्टर पर अब ज़्यादा फोकस कर रहा है. 2022 से पहले एससीओ में जो भी महत्वपूर्ण आर्थिक पहलें शुरू की जाती थीं, रूस उनका समर्थन करने में उत्साह नहीं दिखाता था, क्योंकि रूस को लगता था कि ऐसा करना चीन का पिछलग्गू बनने जैसा है. लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद लगे तमाम प्रतिबंधों और वित्तीय लेन–देन पर लगी रुकावटों की वजह से रूस के नजरिए में बदलाव आया है और वो बीजिंग की आर्थिक परियोजनाओं पर चर्चा करने और उनका समर्थन करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है. चीन के प्रस्तावों का रूस द्वारा खुलकर समर्थन करने का एक उदाहरण उसका तियानजिन समिट में एससीओ विकास बैंक की स्थापना के फैसले के साथ खड़ा होना है.

एससीओ विकास बैंक की यह पहल 2010 में उस वक्त शुरू हुई थी, जब चीन संगठन के सदस्य देशों को कर्ज देने और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी उनकी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बैंक को बढ़ावा देने में जुटा था. बीजिंग ने इस बैंक के स्थापना के प्रस्ताव में एससीओ के सदस्य राष्ट्रों के छोटे व्यवसायों और परियोजनाओं को ऋण देने की बात भी कही थी. जाहिर है कि इससे चीन और बैंक दोनों को खासा मुनाफा होता, लेकिन इससे कहीं न कहीं संगठन के सदस्य देशों के कर्ज के जाल में फंसने का खतरा था. हालांकि, ज़्यादातर मध्य एशियाई सदस्य देशों ने चीन के एससीओ बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था, क्योंकि वे चीन से अपनी विकास परियोजनाओं

के लिए कर्ज लेना चाहते थे. तब रूस एक ऐसा देश था, जिसने चीन के इस प्रस्ताव का विरोध किया था, क्योंकि उसे डर था कि इससे यूरेशियन क्षेत्र में बी. जिंग का आर्थिक दबदबा बढ़ सकता है, जिसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे. रूस ने इसके जवाब में कम पूंजी के साथ एक डेवलपमेंट फंड यानी विकास कोष और एक विशेष अकाउंट की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, जिसके जरिए ऊर्जा, परिवहन और उच्च प्रौद्योगिकी सेक्टर की परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा सके. इतना ही नहीं, तब बीच का रास्ता निकालते हुए मास्को ने अस्ताना स्थित यूरेशियन विकास बैंक (EDB) को एससीओ बैंक के आधार के तौर पर इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव रखा था. जाहिर है कि इससे रूस फायदे की स्थिति में होता, क्योंकि मास्को को उम्मीद थी कि यूरेशियन विकास बैंक में उसका मेजॉरिटी स्टेक होगा यानी बहुमत हिस्सेदारी होगी. वहीं बीजिंग तब ईडीबी में बराबरी की हिस्सेदारी के लिए कोशिश कर रहा था. जाहिर है कि पूर्व में बैंक में हिस्सेदारी और अपने–अपने फायदों को लेकर रूस व चीन आमने–सामने आ चुके हैं, ऐसे में यह निश्चित है कि एक नए वित्तीय संस्थान यानी प्रस्तावित एससीओ विकास बैंक के गठन में भी ये सारे सवाल जरूर खड़े होंगे. जैसे कि पहला सवाल तो यही सामने आएगा कि एससीओ बैंक की स्थापना के दौरान चार्टर पूंजी, यानी कौन सा देश शुरुआत में कितनी पूंजी का योगदान करेगा, या कहा जाए कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा? साथ ही सदस्य देशों के बीच शेयर वितरण किन सिद्धांतों पर आधारित होगा? इसके अलावा, सवाल यह भी पैदा होगा कि जिन परियोजनाओं का वित्तपोषण इस बैंक के द्वारा किया जाएगा, उनके चयन के मापदंड क्या होंगे? हालांकि, रूसी सरकार को उम्मीद है कि ये नया वित्तीय संस्थान न केवल लेनदेन के नए तौर–तरीकों यानी डिजिटल मुद्राओं और डिजिटल वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगा, बल्कि इसका सबसे प्रमुख मकसद पश्चिमी देशों के वित्तीय तंत्र से मुक्ति पाना होगा. जाहिर है कि रूस और चीन एससीओ विकास बैंक को एक नए सिक्योरिटी डिपोजिटरी के रूप में यानी एक ऐसी जगह के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं जो शेयर, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों आदि जैसी वित्तीय प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखेगी और उनके हस्तांतरण व ट्रेडिंग को सुगम बनाएगी. कहने का मतलब है कि ये देश एससीओ विकास बैंक को यूरोक्लियर और क्लियरस्ट्रीम के विकल्प के रूप में उपयोग करने की सोच रहे हैं. इन परिस्थितियों में एससीओ विकास बैंक के परिचालन से जुड़े सवाल और व्यापक हो जाते हैं.

एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना को लेकर चल रही चर्चाओं से एक बात तो एकदम साफ है कि शंघाई सहयोग संगठन के भीतर सबसे प्रमुख भूमिका चीन और रूस की है और ये दोना. ही संगठन का एजेंडा निर्धारित करते हैं और तय करते हैं कि यह कैसे काम करेगा. फिलहाल बीजिंग और मॉस्को में एससीओ विकास बैंक की स्थापना को लेकर कोई मतभेद नजर नहीं आ रहा है, बावजूद इसके एससीओ के दूसरे सदस्य देशों और विशेष रूप से उनकी केंद्रीय बैंकों की ओर से इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाया जाता है, वो इस मामले में अहम भूमिका निभाएगा. बहरहाल, एससीओ विकास बैंक की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और इस प्रस्ताव को वास्तविकता में बदलने के लिए विशेषज्ञों के पास विचार के लिए भेज दिया गया है. यानी फिलहाल एसस. ीओ के इस प्रस्ताव की स्थिति भी ब्रिक्स जैसी हो गई है. रूस ने साल 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार के लिए वैकल्पिक वित्तीय इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन 2025 में ब्राजील की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान इस प्रस्ताव को विचार करने के लिए भेज दिया है, यानी एक तरह से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. इस लिहाज से देखा जाए तो एससीओ विकास बैंक की स्थापना को भी हकीकत बनने में कई साल लग सकते हैं.

जिस तरह से शंघाई सहयोग संगठन का भौगोलिक विस्तार हो रहा है और इसके एजेंडे में नए मुद्दे शामिल हो रहे हैं, उसके मद्देनजर एक ओर जहां संग. ठन की ताकत और क्षमता में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी जि. म्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ती जा रही है. इतना ही नहीं, रूस और चीन एससीओ के अहम सदस्य देश हैं और ऐसे में इस संगठन का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ये दोनों देश अपने द्विपक्षीय मतभेदों को कितने कारगर तरीक से सुलझाते हैं. इसके अलावा, एससीओ का भविष्य इस पर भी निर्भर करेगा की भारत समेत दूसरे सदस्य देश चीन और रूस के प्रस्तावों को कितनी शिद्दत से बगैर किसी शक–सुबह के मंजूरी देते हैं. इस सारी बातों से साफ हो जाता है कि एससीओ का भविष्य कई बातों पर निर्भर है और इसको लेकर आगे भी चर्चाएं चलती रहेंगी. कहने का मतलब है कि वैश्विक स्तर पर भू–रा. जनीति क्या करवट लेती है और भविष्य में दुनिया भर में राजनीतिक व आर्थिक लिहाज से क्या बदलाव आता है, उन पर भी यह निर्भर है कि एससीओ की भविष्य की रूपरेखा और एजेंडा क्या होगा. आ. खिर में, तियानजिन एससीओ समिट के दौरान काफी कुछ हासिल किया गया है और कई मुद्दों पर सदस्य देशों ने आम सहमति के जरिए निर्णय लेकर साबित किया है कि यह संगठन न केवल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि भविष्य की जरूरतों के मुताबिक अपने एजेंडा में बदलाव भी कर रहा है. बावजूद इसके, जिस प्रकार से तियानजिन में एससीओ को एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रखने वाला संगठन बताने को कोशिश की गई और इसको लेकर जो तमाम बड़ी–बड़ी बातें की गईं, यह सब न केवल अवास्तविक प्रतीत होता है, बल्कि संगठन की उपलब्धियों को बहुत बढ़ा–चढ़ाकर पेश करने जैसा भी प्रतीत होता है. **साभार-लेखक,अले. क्सई जखारोव ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम में रूस और यूरेशिया के फेलो हैं.**

चीन-रूस-भारत: नई धुरी की ताकतवर तिकड़ी

ट्रम्प की टैरिफ धौंस–पट्टी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को मुट्ठी में करने की चाहत से दुनिया सामुद्रिक काल–चक्र की तरह फिर पुराने दो–ध्रुवीय दौर में दाखिल होने की कगार पर, लिहाजा चीन के शंघाई में शी जिनपिंग, पुतिन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात अहम बात 1970 के दशक की मध्य की ओर बढ़ते वर्षों की है। अमेरिकी राष्ट्रपति निक. सन की पहली (या किसी भी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली) यात्रा के पहले माहौल तैयार करने उनके बेहद चर्चित तथा जाने–माने कूटनीतिक, विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर बीजिंग पहुंचे थे। दौरे के आखिर में वे चीन के सर्वोच्च नेता, चेयरम. ैन माओ त्से तुंग से मुलाकात करने गए। भेंट छोटी–सी थी। कहते हैं, ज्यादातर वक्त किसिंजर ही बोलते रहे। आखिर में माओ ने हाथ कटोरे जैसा बनाकर कोई मुहावरा बोला। दुभाषिए ने बताया, माओ कह रहे हैं कि अभी हम एक कटोरा भात खाना शुरू किए हैं, वह भी न छीन लेना। तब अमेरिकी अभियान सोवियत ध ुरी को तोड़ने का था। लेकिन अब शी जिनपिंग के दौर में उलटा होने जा रहा है, जो माओ से लगभग विपरीत धारा के हैं। अब शंघाई में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की 31 अगस्त की बैठक में एक ऐसी मोटी लकीर खिंचने जा रही है, जो दुनिया को फिर पुराने दौर जैसी दो ताकतवर धुरियों की ओर ले जा रही है। 27 अगस्त से ट्रम्प ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ दाग कर इसे जैसे पुख्ता कर दिया। इस दो धुरियों में एक ओर अमेरिका की अगुआई में पश्चिम या यूरोप तथा उसके व्यापक दायरे के देश और दूसरी ओर पूरब या यूरेशिया के साथ दक्षिण गोलार्द्घ के देश हो सकते हैं, जो ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और उनके साथ अन्य देश) की छतरी तले इकट्ठा हैं। फिलहाल इस दूसरी धुरी के लिए तीन शख्सियता. े– चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिकड़ी विशाल चुंबकीय ताकत बन रही है, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामापोसा जैसे बड़ी शख्सियतें भी जुड़ने वाली है। इसे संभव किया है अमेरिका के नए हुक्मरान डोनाल्ड ट्रम्प ने, जिनकी खुद के इशारों पर दुनिया को नचाने की फितरत छलकती है।

दरअसल दौर बदलने का यह सिलसिला दुनिया में पहले भी चलता रहा है। इसके पहले वह दौर आधी सदी या कुछेक साल पहले का है, जब दुनिया करवट बदल रही थी। सोवियत सेनाएं अफग. ानिस्तान में घुस चुकी थीं और शायद दुनिया के दो ताकतवर धुरियों में एक 'क्रेमलिन कल्ट' के विशाल किले में दीवारें दरकनी शुरू हो चुकी थीं। उसे ढहने में बेशक एक दशक से कुछ ज्यादा जरूर (या ठीक–ठीक कहें तो 1987–89 में) लगे। उससे पीछे भी या याद करें तो इतने ही वक्त में, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, ये दो धुरियां कायम हुई थीं। उसके पीछे पहले विश्वयुद्ध के दौर में पहुंचे तो, दो धुरियां ऐसे ही आकार ले चुकी थीं, मित्र देश और धुरी राष्ट्रों (जर्मनी, इटली, जपान वगैरह) के रूप में। तो, क्या यूक्रेन युद्ध भी वैसा ही कोई मुकाम है, जिससे कथित एक ध्रुवीय दुनिया का स्मृति–लेख लिखने का सिलसिला शुरू होता है। यूक्रेन पर रूसी हमले की शुरुआत एक मायने में नाटो ताकतों के विस्तार की पहल से हुई थी, जिससे रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन खौवा उठे। और अब अमेरिका के मनमौजी किरदार डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ कूटनीति उसकी आखिरी दीवारें ढहा रही है।

जरा फिर पुराने दौर में लौटिए। सत्तर के उस दशक में किसिंजर और निक्सन भारत भी आए थे और तब की प्रधानमंत्री

इंदिरा गांधी के दो–टूक जवाब से कुछ चिढ़ बैठे थे। यहां भी उलटा हुआ, लेकिन अलग तरह से। अमेरिका की ओर झुकाव अस्सी के दशक के मध्य से बढ़ने लगा। उसकी शुरुआत नब्बे के दशक में आर्थिक उदारीकरण और ग्लोबीकरण से हुई, और बढ़ते–बढ़ते नरेंद्र मोदी के राज में अमेरिका की ओर झुकाव पूरी तरह हो गया। लेकिन ठहरिए, दूसरे दौर में राष्ट्रपति ट्रम्प ने मांगें इंतहा बढ़ाईं तो फिर बाजी पलट गई।

दो धुरियों की मुद्रा

अब रूस–चीन–भारत की तिकड़ी फिर शक्ल ले रही है और सामुद्रिक काल–चक्र की तरह फिर दुनिया उसी पुरानी दो ध ुरियों की ओर लौट रही है, जो आध ी सदी पहले अपने चरम पर थी। अगर शंघाई बैठक में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ब्रिक्स में लूला की पहल जैसी डॉलर के मुकाबले नई मुद्रा या देशों की मुद्राओं के बीच आदान–प्रदान की व्यवस्था बन जाती है, तो यह नई विश्व व्यवस्था आ. कार लेने लग सकती है। इसी बुनियादी वजह से ट्रम्प ब्रिक्स को मरा हुआ बताते रहे हैं। इसके पहले भी नब्बे के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश के इराक के सद्दाम हुसैन से खफा होने की एक बड़ी वजह यह थी कि सद्दाम रूस के साथ व्यापार डॉलर के बदले आपसी मुद्राओं में करने का करार कर रहे थे और बाकी देशों को भी डॉलर के खिलाफ लाइन लेने को कह रहे थे। आखिरकार सद्दाम नेस्तनाबूद कर दिए गए और पश्चिम एशिया, खासकर अरब देशों में अमेरिका का दबदबा बढ़ गया। हालांकि ईरान उसकी दबिश में नहीं आया और कई उथल–पुथल चलते रहे, जो आज भी जारी हैं। आज भी ईरान पर दबिश की बड़ी वजह नई धुरी को बनने देने से रोकना ही है।

इसी तरह भारत पर भी रूस से तेल खरीदने के मामले में दंड स्वरूप 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ थोपने और सेक. ंडरी प्रतिबंधों की धमकी की बड़ी वजह उसे ब्रिक्स और शंघाई शिखर बैठकों से हाथ खींचने पर मजबूर करके नई धुरी की ओर जाने से रोकने के लिए ही लगती है। ट्रम्प प्रशासन ने 27 अगस्त से अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ का नो. टिफिकेशन जारी कर दिया। यानी अब से अमेरिका में भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगेगा। लेकिन शंघाई में अगर फैसला उससे प्रभावित नहीं हो. ता है तो फिर ट्रम्प ही नहीं, यूरोपीय संघ का भी रुख कड़ा होने वाला है। हालांकि चीन और रूस भी वैकल्पिक बाजार तलाश रहे हैं और उनके झुकने की उम्मीद कम है। लूला भी खुलकर अमेरि. का विरोध में खड़े दिखते हैं। दरअसल डॉलर में दुनिया का व्यापार कम होने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही नहीं, यूरोपीय देशों पर भी भारी असर पड़ेगा। दुनिया में उनका दबदबा घट जाएगा।

ट्रम्प–पुतिन वार्ता

ट्रम्प या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश इस खतरे को भांप रहे हैं। इसी वजह से ट्रम्प अलास्का में 15 अगस्त को पुतिन से मिले। वह बातचीत अभी नाकाम तो नहीं हुई, लेकिन फली. भूत होने की संभावना कम दिख रही है। वार्ता युद्ध विराम की घोषणा के बिना ही समाप्त हो गई। नजारा वाशिंगटन में स्थानांतरित हो गया, जहां ट्रम्प ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की और प्रमुख यूरोपीय नेताओं के साथ बा. तचीत की, ताकि शांति समझौते तक पहुंचने के लिए भविष्य की प्रगति की योजनाएं तैयार की जा सकें, जिसका भविष्य जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के कड़े रुख को देखते हुए अनिश्चित है। बड़ी वजह यह भी यूरोपीय देशों का रुख रूस के खिलाफ या यूक्रेन के पक्ष में दिखता है। हाल में कनाडा ने यूक्रेन की करोड़ों डॉलर की मदद की। पुतिन बेमतलब नाक घुसेड़ने के लिए यूरोपीय नेताओं को धमका भी चुके हैं। हाल में उन्होंने कहा, ष्अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन युद्घ को खींचे रखकर रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। जाहिर है, पुतिन चीन पर ज्यादा भ. रोसा कर रहे हैं। चीन ही रूसी तेल और ऊर्जा का फिलहाल सबसे बड़ा खरीददार भी है, लेकिन ट्रम्प उस पर दंडात्मक टैरिफ लगाने की अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं।

भारत का पूर्वी रुख

भारत ट्रम्प की धमकियों के मद्देनजर रूस और चीन की ओर ज्यादा झुका। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को में पुतिन से मिले। पुतिन के इस साल के अंत में भारत आने की संभावना बढ़ गई है। इसके उलट क्वाड की बैठक के लिए ट्रम्प के दिल्ली आने की उम्मीद न के बराबर है। क्वाड हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा घटाने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत का संगठन है और अब लग रहा है कि भारत उस दाय. रे से निकल रहा है। इसका यही मतलब है कि भारत चीन और रूस के पाले में जाता जा रहा है। इसी महीने विदेश मंत्री एस. जयशंकर बीजिंग भी गए और चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए तो दोनों देशों के 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवन घाटी में हुई झड़प के बाद तल्ख रिश्तों में नरमी दिखी। वांग यी ने कहा, "गलवन में वह झड़प नहीं होनी चाहिए थी। हमें जल्दी ही सीमा विवाद पर स्थाई हल की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन व्याप. ारिक रिश्ते या विश्व व्यवस्था में साझी भूमिका में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।

ट्रम्प की खीझ

अमेरिका को, जाहिर है, ये बातें नहीं सुहाती हैं। हाल में ट्रम्प प्रशासन ने अपने बेहद करीबी दबंग सहयोगी सर्गेई गोर को भारत का राजदूत बनाया है और उन्हें ज्यादा ताकत देने के लिए दक्षिण एशिया का समन्वयकर्ता भी बनाया है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने एक्स पर लिखा, "गोर की नियुक्ति का मतलब है कि ट्रम्प भारत को और कसना चाहते हैं।

ट्रम्प के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी है कि ट्रम्प और पुतिन के बीच अलास्का वार्ता नाकाम हो जाती है, तो भारत पर और भी ज्यादा टैरिफ जुर्माना लगाया जाएगा। वे यह भी चाहते हैं कि यूरोपीय संघ भारत पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए। यूरोपीय संघ पहले ही भारत की कंपनी न्यारा एनर्जी पर प्रतिबंध लगा चुका है, जिसमें रूस की रोसनेफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी है। यही नहीं, सस्ते तेल की खरीद के लिए अंबानी की रिलायंस पर भी प्रतिबंध लग सकता है। यह समझ से परे लगता है कि यूक्रेन मुद्दे को सुलझाने में अमेरिका की नाकामी के लिए भारत को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है। मतलब वही है कि भारत को दूसरी धुरी की ओर बढ़ने देने से रोकना है।

भारत की दुविधा

हालांकि ट्रम्प की बात नहीं मानने से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कॉरपोरेट घराने पहले ही सरकार को गंभीर परिणामों की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल इस दौरान कॉरपोरेट घरानों का रिश्ता अमेरिका और यूरोपीय देशों से कुछ ज्यादा हो गया है। यह बड़ी दुविधा है और सरकार के भीतर व्यावहारिक लोगों का मानना है कि भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करना होगा। यही नहीं, ट्रम्प को खुश करने के लिए भारत को अमेरिका से और तेल और रक्षा उपकरण खरीदने होंगे। लेकिन 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद स्थितियां उलट गई हैं।

यह सही है कि मोदी सरकार की विदेश नीति में अमेरिका झुकाव एक कमजो. री रही है। अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकियों की एक लंबी पृष्ठभूमि रही है। 1998 में भारत के पोकरण परमाणु परीक्षणों के कारण अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन 2001 में 9ध्11 के हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत वाशिंग. टन का नया सहयोगी बन गया। भारत तब भी वाशिंगटन का मित्र बना रहा जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 2004 के चुनावों में हार गई और उसके बाद मन. मोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रग. तिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार आई। उसने 2008 में अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौता किया।

ट्रम्प के पहले कार्यकाल में मोदी सर. कार ने अमेरिका और भारत के बीच तालमेल को और पुख्ता किया। उसके बाद बाइडन सरकार ने इस सौ. हार्द पर थोड़ा ब्रेक लगाया। वजह यह थी कि सितंबर 2019 में टेक्सास के ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में उन्होंने "अबकी बार, ट्रम्प सरकार" का नारा लगवाया था। लेकिन इस साल दूसरी बार ट्रम्प लौटे तो उनके आगे श्मेक अमे. रिका ग्रेट एगेनश (मागा) का एजेंडा था और उनके मागा समर्थकों के लिए भारत का, खासकर कृषि और डेयरी उत्पादों का बाजार अहम था, लेकिन मोदी के लिए उसे खोलने पर घरेलू राजनीति में मुश्किलें थीं। सो, मामला गड़बड़ा गया।

शंघाई का एजेंडा

खैर, शंघाई में जुटी तिकड़ी को पारंपरिक आर्थिक मुद्दों के अलावा समग्र रणनी. ति में बदलाव की तलाश करनी होगी। उन्हें व्यापक डिजिटल आर्थिक व्यवस्था भी बनानी होगी, ताकि इस मामले में पश्चिमी देशों पर निर्भरता घटे। ऐसी विदेश नीति भी बनानी होगी, जो निवेश वाले अन्य देशों के साथ अपने संबंधों में आर्थिक पहलू पर जोर दे। कुछ रणनी. तिक फेरबदल भी करना होगा। जैसे, वांग यी भारत के बाद फौरन पाकिस्. तान गए और चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक पनडुब्बियों की सौगात भी दी। रूस भी पाकिस्तान को मदद मुहैया करा रहा है। इन तमाम मामलों में एक संतुलित रवैया भारत को भी अपनाना पड़ सकता है और पुराने रवैयों में तरमीम करना पड़ सकता जो आसान नहीं होगा।

इसके अलावा, भारत के मौजूदा विश्व नजरिए में भी बदलाव की दरकार हो सकती है। मसलन, यह पूरब और दक्षिण ी गोलार्द्ध की ओर रुख अमेरिका के साथ निकटता के पहले वाले रुख के विपरीत है। मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ब्रिक्स देशों ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के फिलस्तीन के प्रति दिखाई गई एकजुटता के संदर्भ में अलग रही है। इसमें भारत का इज्राएल की पैरोकारी भी बदलनी पड़ सकती है। गाजा में चल रहे नरसंहार पर रुख भी बदलना पड़ सकता है। बहरहाल, इन तमाम दिक्कतों और बाधाओं के बावजूद अगर दुनिया में नई धुरी तैयार होती है तो नई विश्व व्यवस्था और नए टकरावों के दरवाजे भी खुल सकते हैं। तो, सबकी नजर अब शंघाई पर होगी।

courtesy–www.outlook.com

नेपाल का 'जेन जी' आंदोलन

नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया पर बैन और कथित राजनीतिक भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन में कई लोगों की मौत के बाद आलोचना का सामना कर रहे गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

उन्होंने सोमवार रात प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा सौंप दिया. हालाँकि, बैठक में शामिल दो मंत्रियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है.

वहीं दिन में युवाओं और पुलिस के बीच झड़पों में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है. देशभर में कुल 19 लोगों की मौत हुई है.

पुलिस के हवाले से बीबीसी नेपाली सेवा के संवाददाता ने बताया कि काठमांडू के अलावा पूर्वी शहर इटहरी में दो लोगों की मौत हुई है. अधिकतर घायलों को न्यू बनेश्वर स्थित सिविल सर्वेंट्स अस्पताल ले जाया गया है.

काठमांडू से स्थानीय पत्रकार नरेश ज्ञवाली ने फोन पर बीबीसी हिंदी के संवाददाता दिलनवाज पाशा को बताया, कम से कम डेढ़ सौ घायलों को अलग. –अलग अस्पतालों में ले जाया गया.

उन्होंने आगे कहा, कई जगहों पर कर्फ्यू लगा है, सेना भी सड़क पर है, भारी झड़पें हुई हैं. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे हैं और मौत की रिपोर्ट्स आने के बाद भी प्रदर्शन जारी हैं.

प्रशासन ने कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया है. खुद को जेन जी यानी नई पीढ़ी बताने वाले प्रदर्शनकारी सिस्टम में फैले कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा रहे हैं.

इस बीच नेपाल के सूचना मंत्री ने ऐसे संकेत दिए हैं कि सोशल मीडिया बैन के फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है.

युवाओं का प्रदर्शन, सड़क पर सेना

सोमवार सुबह हजारों प्रदर्शनकारी काठमांडू के सिंह दरबार में इकट्ठा हुए और फिर न्यू बनेश्वर स्थित संसद भवन की ओर बढ़े. बीबीसी संवाददाता केशव कोइराला के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर संसद भवन परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान झड़पें हुईं और पुलिस ने बल प्रयोग किया.

राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास, नारायण दरबार संग्रहालय, प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन के आसपास रात दस बजे तक कर्फ्यू रहेगा. प्रवक्ता के अनुसार, प्रदर्शनकारी अराजक हो गए हैं और निषेधाज्ञा तोड़ रहे हैं.

कर्फ्यू बढ़ाने की घोषणा के तुरंत बाद नेपाल सेना की टुकड़ी सड़कों पर तैनात कर दी गई. नेपाल सेना के प्रवक्ता सहायक जनरल राजाराम बसनेत ने कहा, लिखित आदेश मिलने के बाद एक छोटा सैन्य दल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेजा गया है.

अधिकारियों का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की. इस दौरान हिंसा की रिपोर्ट्स हैं और कई घायलों को अस्पताल ले जाया गया.

नेपाल से आ रही तस्वीरों और वीडियो में हजारों प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं. प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा के हाथ में बैनर था, जिस पर लिखा था, भूकंप की जरूरत नहीं है, नेपाल रोज भ्रष्टाचार से हिलता है.

युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे. कुछ महीने पहले नेपाल में राजशाही बहाल करने के लिए भी आंदोलन हुआ था. उस दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने सिस्टम में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था.

सोशल मीडिया पर बैन

नेपाल सरकार ने बीते सप्ताह 26 प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था. इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप जैसे चर्चित सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं.

सरकार का कहना है कि सोशल मी. डिया कंपनियों को देश के कानूनों का पालन करने, स्थानीय दफ्तर खोलने और ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था.

चीन की सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक ने समय रहते इन शर्तों का पालन कर लिया, इसलिए टिकटॉक पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया.

नेपाल में बड़ी संख्या में लोग विदेशों में रहते हैं. मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया पर बैन के बाद विदेशों में रह रहे नेपाली नागरिकों को परिवार से संपर्क करने में दिक्कतें आ रही हैं.

बैन के बाद प्रदर्शन का आह्वान

सोशल मीडिया वेबसाइटों पर प्रतिबंध के बाद युवाओं ने प्रदर्शन का आह्वान किया. नेपाल में इस समय टिकटॉक चल रहा है. आयोजकों ने टिकटॉक पर कई वीडियो शेयर कर युवाओं से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की.

टिकटॉक पर 'नेपो बेबी' ट्रेंड भी चलाया गया, जिसमें नेताओं के बच्चों के ऐशो–आराम भरे जीवन की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए गए. इसमें सवाल उठाया गया कि राजनेता अपने बच्चों को तो फायदा पहुंचा रहे हैं लेकिन देश के लिए काम नहीं कर रहे.

कई वीडियो में नेपाल के दूर–दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के कठिन जीवन और नेताओं के आरामदायक जीवन की तुलना भी की गई.

बीते गुरुवार नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लागू किया था. इसके बाद से युवा इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं.

हालांकि इन प्रदर्शनों का कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं है, लेकिन कई युवा समूह भीड़ जुटा रहे हैं. ये समूह कार्रवाई का आह्वान और ऑनलाइन अपडेट जारी कर रहे हैं.

नेपाल के प्रमुख शहरों काठमांडू, पोखरा और इटहरी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को वर्दी पह. नकर और किताबें हाथ में लेकर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है. सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में स्कूली बच्चों को भी मार्च में हिस्सा लेते हुए दिखाया गया है.

प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या हैं?

उनकी दो मांगें बिलकुल साफ हैं. पहली– सरकार सोशल मीडिया से तुरंत प्रतिबंध हटाए, दूसरा– प्रदर्शनकारी जिन श्भ्रष्ट कार्यप्रणालीश की बात कर रहे हैं अधि ाकारी उसे तुरंत रोकें.

प्रदर्शनकारियों में अधिकतर कॉलेज के छात्र शामिल हैं, जो सोशल मीडिया पर रोक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाला बताते हैं.

एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा बीनू केसी ने बीबीसी नेपाली से कहा, ष्हम नेपाल में भ्रष्टाचार को खत्म होते देखना चाहते हैं.ष ष्चुनावों के दौरान नेता वादा करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते. वे बहुत सी

समस्याओं की जड़ हैं.

वह आगे कहती हैं कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है क्योंकि इससे ऑनलाइन क्लासेज और पढ़ाई की सामग्री तक सीमित पहुंच हुई है.

एक कंटेंट क्रिएटर सुभाना बुधाथोकी ने कहा, जेन जी अब नहीं रुकेगा. यह प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर ही नहीं है. यह हमारी आवाज दबाने को लेकर है और हम यह होने नहीं देंगे.

देश भर में पुलिस की निगरानी

पाल पुलिस सिर्फ काठमांडू ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में निगरानी कर रही है. पुलिस प्रवक्ता बिनोद घिमिरे के अनुसार, सोमवार सुबह से काठमां. डू और कई प्रमुख शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं.घिमिरे ने बीबीसी न्यूज नेपाली से कहा, सिर्फ काठमांडू ही नहीं, कई और शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं. पुलिस बल इनकी निगरानी कर रहा है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर पहलू का ध्यान रखते हुए योजना बनाई गई है और बल तैनात किए गए हैं.

फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है?

नेपाल सरकार में सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने कहा है कि सोशल मीडिया प्रतिबंध के फैसले पर पुनर्विचार करने को लेकर चर्चा चल रही है.

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है. सूचना और प्रसारण मंत्री गुरूंग ने बीबीसी न्यूज नेपाली से कहा कि इस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी.उन्होंने कहा, जनता की जान से बड़ा सरकार का कोई फैसला नहीं हो सकता. हमारे लिए जनता की जान सबसे अहम है. अगर जरूरत पड़ी तो सरकार के नीतिगत फैसलों पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है. अड़े रहने का कोई मतलब नहीं है.

मंत्री गुरूंग ने यह भी कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन इस पर बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा है, बातचीत हो रही है. मंत्रिपरिषद कोई न कोई निर्णय जरूर करेगी.

नेताओं की प्रतिक्रिया

इस प्रदर्शन को लेकर अलग–अलग तरह का नजरिया सामने आ रहा है. कुछ लोग इसे नई पीढ़ी की श्राजनीतिक चेतनाश बता रहे हैं, जबकि सत्ताधारी दलों का कहना है कि इस प्रदर्शन का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

युवाओं के बीच लोकप्रिय काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शन का समर्थन किया है.

नेपाल की पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल श्प्रचंडश ने कहा है, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर रोक के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन स्वाभाविक है.ष

उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा है, आज जेन–जी पीढ़ी के प्रदर्शन के दौरान हुई दुखद घटना ने मुझे स्तब्ध और गंभीर बना दिया है. पुलिस की गोली से मारे गए युवाओं को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ.

प्रदर्शन से ठीक पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस ओर इशारा किया था कि श्जेन जीश पीढ़ी का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है.

नोट-प्रस्तुत स्टोरी wwwbbc.com **की तत्कालीन रिपोर्टिंग है।**

Courtesy www.bbc.com

130वां संविधान संशोधन विधेयकरू महज फसाना मकसद?

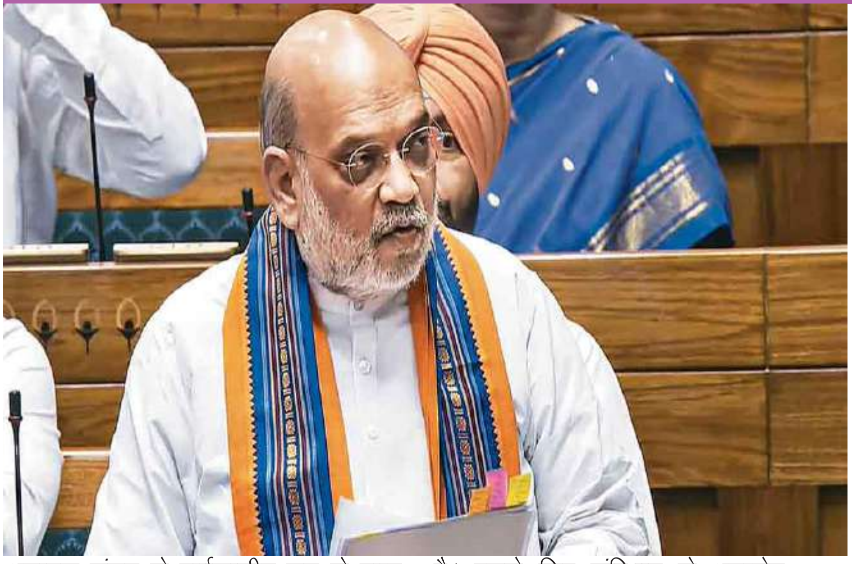

अचानक संसद के वर्षाकालीन सत्र के खत्म होने की पूर्व–संध्या पर 20 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिसकी सुगबुगाहट तक नहीं थी। यही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि उसके पहले की शाम तक लोकसभा सचिवालय को भी इसकी जानकारी नहीं थी। विपक्ष को भी आखिरी मौके पर उसकी प्रतियां मिलीं। फिर, उसके मजमून में ही तय है कि उसे समीक्षा के लिए दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया जाए। ऐसे में सवाल उठा कि इस मौके और वक्त पर विधेयक पेश करने का सियासी मकसद क्या हो सकता है और क्यों इसका ताल्लुक मौजूदा राजनै. तिक हालात से है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इसके सरकारी पक्ष की मंशा पर सवाल उठाकर इसे विपक्ष शासित राज्यों को अस्थिर करने तथा क्षेत्रीय दलों पर दबाव बढ़ाने का औजार बताया।

दरअसल विधेयक में प्रस्ताव है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्री ऐसे आपराधिक मामले में हिरासत में लिए जा सकते हैं, जिसमें पांच साल या उससे ज्यादा सजा हो सकती हो और उन्हें 30 दिन के भीतर जमानत न मिल सकती हो। ऐसी स्थिति में उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। प्रावधान यह भी है कि जमानत मिल जाती है, तो पद फिर मिल सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल की सहमति हो। ये प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव है, क्योंकि अब तक सिर्फ दोषसिद्ध होने पर ही पद से हटने की व्यवस्था है। मंत्री पद पर शामिल करना भी मंत्री परिषद के अधीन है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239ए में संशोधन का प्रस्ताव है। संवैधानिक व्यवस्था को उलटने की वजह से ही विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है। अलबत्ता विधेयक संसद के मौजूदा संख्या बल में पास नहीं हो सकता, बशर्ते सियासी समीकरण न बदल जाएं। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो–तिहाई बहुमत से पास होना जरूरी है। फिर कम से कम 15 विधानसभाओं में अनुमोदन भी जरूरी है। फिलहाल सत्तारूढ़ एनडीए के पास न लोकसभा, न राज्यसभा दोनों में ही दो तिहाई बहुमत नहीं है। इसके अलावा, संविधान के मूल सिद्धांत में बदलाव की वजह से उसे न्यायिक समीक्षा से भी गुजरना पड़ सकता है। इस तरह, शायद यह भी 129वें संविधान संशोधन विधेयक की तरह ही फिलहाल प्रस्ताव भर बनकर रह जाए, जिसमें एक राष्ट्र, एक चुनाव का जिक्र है।

लेकिन इस मौके पर इसे लाने के सियासी मायने भी फौरन स्पष्ट हो गए। बिहार के गया की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त होना चाहती है, लेकिन विपक्ष को इसमें आपत्ति है। अमित शाह भी एक रैली में बोले, ''क्या जेल से सरकार चलाई जानी चाहिए।'' वे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे, जो कई महीने तक जेल से ही सरकार चलाते रहे और जमानत पर छूटने के बाद ही इस्तीफा दिया था। इसी तरह तमिलनाडु में मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालीन ने उन्हें हटाया नहीं था। गृहमंत्री ने इन्हीं मामलों का संसद में भी हवाला दिया था। हालांकि झारखंड के मुख्मंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था। इन मामलों में अदालतों ने जमानत मंजूर करने के लिए प्राथमिक सबूत तक न होने के लिए ईडी को फटकार लगाई थी।

दरअसल इस विधोयक के खिलाफ विपक्ष की शंकाएं इस वजह से भी हैं कि पिछले दस साल में ईडी और सीबाआइ के करीब 5,900 मामलों में सिर्फ 8 में दोष सिद्ध हो पाए। विपक्षी नेताओं के खिलाफ 950 से ज्यादा मामलों में सिर्फ दो में सजा सुनाई जा सकी। हाल में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ अदालत ने सबूत न होने पर मामला बंद कर दिया, जबकि उन्हें ढ़ाई साल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बिताने पड़े। इसलिए शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत कहते हैं कि अगर यह कानून बन गया, तो किसी भी शिकायत पर कोई थानेदार गिरफ्तार कर लेगा। उनके मुताबिक, ''जहां भाजपा वोट चोरी से चुनाव नहीं जीत सकती, वहां ऐसे कानून से सरकार लूट की योजना बना रही है।''

विपक्ष, खासकर इंडिया ब्लॉक की सभी राजनैतिक पार्टियां तो इस कदर खिलाफ हैं कि लोकसभा में जब अमित शाह इसे पेश कर रहे थे, तो विपक्षी बेंचों से इसकी प्रतियां भी फाड़कर उनकी ओर उछाल दी गईं। तृणमूल कांग्रेस ने, तो इसकी समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति में न शा. मिल होने का ऐलान कर दिया है। उसके राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि असंवैधानिक विधेयक की समीक्षा नाटक के अलावा कुछ नहीं है।

संभव है, इसके जरिए सत्तारूढ़ भाजपा और एनडीए का एक सियासी मकसद भ्रष्टाचार के मसले पर विपक्ष को घेरने का हो, क्योंकि विपक्ष बिहार में एसआइआर को लेकर विपक्षी महागठबंधन अपनी वोटर अधिकार यात्रा में ''वोट चोरी'' के आरोप उछाल रहा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जरिए चुनाव जीतने के विपक्ष के आरोपों की काट के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन को शायद भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना मुफीद लग रहा है। हालांकि कांग्रेस के सांसद वेणुगोपाल का यह भी आरोप है कि इस विधायक के जरिए भाजपा अपने सहयोगियों, जनता दल (यूनाइटेड) और तेलुगु देशम को डराना चाह रही है, जो कई मुद्दों पर नाराज चल रहे हैं। इतना तय है कि यह सियासी शह–मात के खेल का ही हिस्सा है।

मोदी सरकार के 11 साल : तीन बड़े कदम ने बदल दी 'आम' जिंदगी

9 जून को सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। यह जनता का विश्वास है, जो लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में बने हुए हैं। पिछले 11 सालों में दुनिया ने भारत की आर्थिक और सामरिक शक्ति को देखा है, लेकिन गरीब कल्याण को लेकर नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की, जो युग परिवर्तनकारी हैं।

इस साल की शुरुआत में महाकुंभ प्रयागराज में था। वहां छोटे से छोटा रेहड़ी वाला भी यूपीआई पेमेंट ले रहा था। एक बार एक रेहड़ी वाले से बातचीत में पता चला कि उसके अकाउंट में एक लाख से ऊपर रुपए की बचत हो गई है, क्योंकि यूपीआई से आए पेमेंट के अधिकांश हिस्से को वह बचत के रूप में सुरक्षित कर लेता है। कैश से ही कारोबार को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। पहले शायद उसके लिए यह संभव नहीं था। यह चमत्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन–धन योजना और डिजिटल पेमेंट की क्रांति के कारण संभव हो पाया है। यदि जन–धन योजना में गरीब रेहड़ी वाले का बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर न खुलता तो शायद वह कभी बैंक खाता खोलने का सपना नहीं देख पाता।

मोदी सरकार का यह तीसरा कार्यकाल चल रहा है। 9 जून को सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। यह जनता का विश्वास है, जो लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में बने हुए हैं। पिछले 11 सालों में दुनिया ने भारत की आर्थिक और सामरिक शक्ति को देखा है, लेकिन गरीब कल्याण को लेकर नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की, जो युग परिवर्तनकारी हैं।

बदलती देश की तस्वीर

अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री बनने के चंद महीने बाद नरेंद्र मोदी ने जन–धन योजना की शुरुआत की। इसमें जीरो बैलेंस में बैंक खाता खोला गया। शुरुआत में विपक्ष ने इस योजना को लेकर मोदी सरकार का उपहास उड़ाया, लेकिन योजना के तहत 55 करोड़ से ऊपर खाते खुले, जिनमें ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्र के लगभग 36.63 करोड़ खाते हैं। इन खातों में 2.30 लाख करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। अच्छी बात है कि 55.6ः यानी 29.37 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। यह भी सच है कि दिसंबर 2023 में 20ः खाता निष्क्रिय थे। हालांकि, निष्क्रिय खातों में भी 12,779 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में जब क्रांति आई तो सबसे बड़ा गेम चेंजर यूपीआई पेमेंट बना। यूपीआई से रुपये सीधे बैंक खाते में जाता है। यदि इतनी बड़ी संख्या में बैंक खाते न खोले गए होते तो शायद यूपी.आई पेमेंट को भी सफल नहीं किया जा सकता था। मुझे याद है, जब मैं किशोर था और उत्तर प्रदेश में अपने गांव जाता था, तब गांवों के अधिकांश लोग खुले में

शौच के लिए जाया करते थे। महिलाओं के लिए तो शौच जाने का एक निश्चित समय निर्धारित था। या वो अलसुबह अंधेरे में या शाम को सूरज छिपने के बाद शौच के लिए खेतों में जा सकती थीं। इससे ज्यादा पीड़ादायक उनके जीवन में कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार पहली बार स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना लेकर आई, लेकिन ईमानदारी से किसी ने इस मिशन को पूरा किया तो वह यही सरकार है। 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। आज 9.63 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। यह एक ऐसा कदम है, जिसने महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। भारत के सिर से एक कलंक भी मिट गया।

बदलती राजनीति

अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आने से पहले मुझे याद है, जब भी मैं सड़क मार्ग से एक से दूसरे शहर की यात्रा करता था, एक सिंगल रोड हुआ करती थी। यात्रा बड़ी कष्टदायक और जोखिम भरी होती थी। भले टोल टैक्स नहीं था, लेकिन यह सफर मुश्किल होता था। वाजपेयी सरकार ने देश में कुछ हाईवे बनाने की शुरुआत की, जिनमें दिल्ली–आगरा, दिल्ली–जयपुर जैसे हाईवे शामिल हैं, लेकिन वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में सड़कों की सूरत बदली है। अच्छी सड़कों ने न्यू इंडिया में गेमचेंजर का काम किया है। भले हमारी जेब से टोल टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन आज कनेक्टिविटी के मामले में भारत विकसित देशों से पीछे नहीं है। देश में एक्सप्रेस–वे और हाई–वे का जाल बिछा हुआ है। अच्छी सड़कों का लाभ खास के साथ आम भारतीय को भी हुआ है।

हालांकि, कुछ विफलताएं भी मोदी सरकार के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बेरोजगारी प्रमुख है। बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रहती है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से 2024 के बीच शहरी युवा बेरोजगारी दर 15 से 23ः तक पहुंची। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बेरोजगारी के वास्तविक आंकड़े जारी नहीं कर रही है। एक बड़ा मुद्दा आज भी वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी का है। उस समय सरकार ने यह कहते हुए नोटबंदी की गई थी कि काले धन पर प्रहार किया जा रहा है। नकली नोटों को रोकना है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। डिजिटल भुगतान तो बढ़ा, लेकिन आज भी बड़ी मात्रा में कालाधन और नकली नोटों का मिलना जारी है। राजनीतिक मोर्चे की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने अपने पहले दो कार्यकाल पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में सफलतापूर्वक चलाए। तीसरे कार्यकाल में वो अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। वैसे, पिछले एक साल में सरकार चलाने का तरीका लगभग वही है, जो पहले दो कार्यकाल में था। सरकार के दो प्रमुख सहयोगी दल जनता दल (यू) और तेलुगू देशम पार्टी सरकार को पूरा सहयोग दे रहे हैं। बिहार मे विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के बाद क्या समीकरण बनते हैं, यह देखना होगा। तेलुगू देशम पार्टी भी सरकार के पक्ष में दिखती है, लेकिन क्या वह आगे चार साल सरकार को यूं ही सहयोग देती रहेगी, यह बड़ा प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे सुखद बात यह है कि विपक्ष की भूमिका बेहद निराशाजनक है। विपक्ष मूल मुद्दों पर सरकार को घेरने के बजाय नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलता है, जिसका लाभ नरेंद्र मोदी को ही हो रहा है।

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

बिहार: सर की सियासत

शक्ति प्रकाश
बिहार ब्यूरो प्रमुख

बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार में इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन के नेता 16 दिनों में 23 जिलों की 1,300 किलोमीटर की यात्रा पर निकले। 17 अगस्त को सासाराम से यात्रा की शुरू हुई, तो राहुल के अलावा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवाद. ी–लिबरेशन) के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी और भाकपा तथा माकपा के नेता मौजूद थे, जो पूरी यात्रा में साथ चले। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। यह मतदाता अधिकार यात्रा राज्य में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनर्रीक्षण (एसआइआर) अभियान में 'मताधिकार से वंचित करने वाली कवायद' के खिलाफ है।

चुनाव आयोग के मुताबिक, इस अभियान का उद्देश्य मृत, नकली, प्रवासी मतदा. ताओं और अवैध घुसपैठियों को मतद. ाता सूची से हटाना है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि एसआइआर का उद्देश्य केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अगुआई वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हितों के अनुरूप मतदाता सूची में हेराफेरी करना है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश इस यात्रा को "बिहार में लाखों मतदाताओं को एसआइआर के जरिए मताधिकार से वंचित करने की भाजपा की चाल" और "देश भर में हो रही 'वोट चोरी' के चा. ाने वाले खुलासों" का जवाब बताते हैं। रमेश कहते हैं कि यह "एक और राजनी. तिक यात्रा" नहीं, बल्कि "नैतिक और संवैधानिक धर्मयुद्ध" है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मतदाता सूची में शामिल लोगा. ें की नागरिकता का पता लगाने का प्रयास कर रही एसआइआर प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता पर फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है लेकिन अदालत ने अपने अंतरिम आदेशों में चुनाव आयोग को आधार कार्ड को शामिल स्वीकृत दस्तावेजों में शामिल करने और ड्रफ्ट सूची में नहीं जुड़े वोटरों की फेहरिस्त जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के दो अंतरिम आदेशों ने स्वाभाविक रूप से विपक्षी खेमे या इंडिया ब्लॉक में अलग तरह का उत्साह भर दिया है, जिसका बिहार का महागठबंधन भी हिस्सा है।

चुनाव आयोग को आदेश दिया गया है कि वह उन 65 लाख मतदाताओं का विवरण अपलोड करे, जिनके नाम बिहार की ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें 22 लाख ऐसे मतदाता भी शामिल हैं, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उसे ऐसे फॉर्मेट में मुहैया कराएं, जिसमें ''एपिक नंबर के जरिए खोज'' संभव हो और नाम हटाने की वजह भी बताई जाए। यह आदेश चुनाव आयोग के लिए झटका है। एपिक नंबर चुनावी फोटो पहचान पत्र में होता है।

चुनाव आयोग ने अदालत में सूची से बाहर किए गए नामों का विवरण उजागर करने के खिलाफ अजीबोगरीब ढंग से तर्क देते हुए कहा कि बाहर किए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करना किसी भी कानून के तहत जरूरी नहीं है। इसके अलावा, हाल ही में, चुनाव आयोग की वेबसाइट ने लगभग रातोरात मसौदा मतदाता सूची का प्रारूप ही बदल दिया। पहले इस प्रारूप में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एपिक नंबर डाल करके व्यक्ति को खोजा जा सकता था। इस कदम ने विपक्षी दलों के साथ–साथ पारदर्शिता और लोकतांत्रिक अधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों ने भी इस कदम की आलोचना की। आयोग ने जिस नए प्रारूप में सूची को बदला, उसमें अब एपिक नंबर डाल कर किसी का नाम नहीं खोजा जा सकता है। विपक्ष का

कहना है कि डिजिटल दस्तावेजों पर एपिक नंबर आधारित खोज रहनी चाहिए क्योंकि इससे त्रुटियों की पहचान करना या दावों को सत्यापित करना आसान हो जाता है। अदालत ने भी इस पर सहमति व्यक्त की है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि वह मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों की सूची का यथासंभव व्यापक प्रचार करे और मतदाताओं को पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को भी शामिल करे, क्योंकि यह जनता के पास मौजूद सबसे आम दस्तावेजों में से एक है। चुनाव आयोग इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा था क्योंकि आयोग का तर्क है कि आधार अविश्वसनीय है और इसमें अक्सर जालसाजी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोई भी दस्तावेज फर्जी हो सकता है, इसलिए यह आधार को न मानने का कोई तर्क नहीं हो सकता।

विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच विवाद नया नहीं है। विपक्ष ने पहले भी कई बार चुनाव आयोग पर सरकार के प्रति झुकाव का आरोप लगाया है, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन पर नेताओं के खिलाफ कार्रवाई से लेकर मतदान प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं तक के मुद्दे शामिल हैं।

तीन चुनाव आयुक्तों में से दो की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने की है, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी शामिल हैं। यह नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत है। हालांकि इस कानून की संवैधानिक वैधता की जांच अभी भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता, राहुल गांधी ने कर्नाटक में मतदाता सूची में पहले भी किए गए हेरफेर को उजागर करने का दावा किया है। इस दावे ने विपक्षी अभियान को और अधिक मजबूत कर दिया है।

जून के अंत में एसआइआर की घोषणा से पहले, विपक्ष ने बिहार में एनडीए की नीतीश कुमार सरकार पर कुशासन का आरोप लगाया था। अब वह मतदाताओं से ''भाजपा और चुनाव आयोग की खुली मिलीभगत'' के खिलाफ ''लामबंद'' होने का आह्वान कर रहा है।

विपक्ष की महारैली जहां रोजगार, बढ़ते अपराध ग्राफ, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को भी उठा रहा है वहीं इसमें, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण और आरक्षण की सीमा को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करना भी शामिल है। निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास के मुद्दे पर रैली का नाम इसके फोकस को दर्शाता है, ''लोगों के मतदान के अधिकार की रक्षा।'' रैली का मुख्य नारा ही है, ''वोट चोर, गद्दी छोड़।''

चालें और रणनीति

बिहार के सत्ताधारी गठबंधन ने भी विकास और जनसंख्या की संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोहरी रणनीति अपनाई है। नीतीश कुमार विकास पर ही ध्यान केंद्रित रखे हुए हैं। घोषणाओं की झड़ी लगाते हुए उन्होंने पेंशनभोगियों और महिलाओं के लिए नकद लाभ बढ़ा दिए हैं, रसोइयों, चौकीदारों और प्रशिक्षकों सहित स्कूल के सहायक कर्मचारियों का मानदेय दोगुना कर दिया है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है, मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पेंशन बढ़ा दी है, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए मौजूदा 35 प्रतिशत आरक्षण को केवल बिहार के स्थायी निवासियों तक सीमित कर दिया है, सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है और बिहार में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है।

भाजपा बिहार के विकास में मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के योगदान को उजागर करने के साथ–साथ अपने घुसपैठ विरोधी अभियान को और भी तेज करने की तैयारी कर रही है। यह बात मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान स्पष्ट हो गई, जिसमें उन्होंने देश की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए "पूर्व–नियोजित षड्यंत्र के हिस्से के रूप में" अवैध प्रवासन के बारे में देश को चेतावनी दी।

2014 से ही मोदी भारत के पड़ोसी देशों से आए अवैध मुस्लिम प्रवासियों के लिए 'घुसपैठिए' शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं, जबकि बिना दस्तावेज वाले हिंदू प्रवासियों के लिए वे 'शरणार्थी' शब्द का इस्तेमाल करते हैं। घुसपैठ से प्रभावित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और प्रगति के लिए खतरा बताते हुए, उन्होंने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च–स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन की घोषणा की है।

दिलचस्प बात यह है कि एसआईआर, बांग्लादेश और म्यांमार मूल के अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए भाजपा शासित विभिन्न राज्यों में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बीच आया है। यही वजह है कि एसआईआर के जरिये मतदाताओं की नागरिकता सत्यापित करने के घोषित उद्देश्य से संदेह बढ़ा है। ऐसा इसलिए कि यह राष्ट्रव्यापी नागरिकता जांच प्रक्रिया के अलावा कुछ नहीं है, जिसका वादा भारत की सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी ताकतें बार–बार करती रही हैं।

भट्टाचार्य के अनुसार, निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के उद्देश्य के रूप में मतदाता सूची से 'विदेशी नागरिकों' को बाहर करने का उल्लेख और मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 'जनसांख्यिकीय मिशन' का आह्वान दर्शाता है कि एसआइआर वास्तव में मतदाता सूची संशोधन की आड़ में नागरिकता–जांच का अभ्यास भर है।

भट्टाचार्य, जिनकी पार्टी के बिहार विधानसभा में 12 विधायक हैं, कहते हैं, ''एसआइआर के तहत अब तक लगभग 65 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। हालांकि, इनमें एक भी नाम विदेशी नागरिक का नाम नहीं दिखाया गया है।''

जमीनी स्तर पर, बिहार के विपक्षी दल इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि मतदाता के रूप में अपनी वैधता साबित करने में विफल होने के मतदान के अधिकार के नुकसान से कहीं अधिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चुनाव अधिकारियों के पास व्यापक शक्तियां हैं, जिनमें संदिग्ध विदेशी नागरिकों के मामलों को सक्षम अधिकारियों को भेजना

भी शामिल है। 'संदिग्ध मतदाता' से कोई भी व्यक्ति जल्द ही 'संदिग्ध नागरिक' बन सकता है। इसके विपरीत, भाजपा लोगों को यह बताने में व्यस्त है कि कैसे विपक्षी दल "केवल अपने घुसपैठिए वोट बैंक को बनाए रखने के लिए" राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमों को रो. कने पर तुले हुए हैं।

बिहार से आगे

बिहार के पड़ोसी पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की लड़ाई तेज हो गई है। यहां कथित घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तन 2014 से भाजपा का प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहा है। बंगाल में भी चुनाव होने में साल भर से कम बचा है। वहां भी चुनाव आयोग ने बंगाल प्रशासन से, एसआईआर की तैयारी करने को कहा है।

राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गुट का हिस्सा है, एसआईआर का विरोध कर रही है। पार्टी की लोकसभा सांसद महुआ मो. इत्रा उन याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं, जिन्होंने एसआइआर प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय के 14 अगस्त के अंतरिम आदेश का स्वागत करते हुए, टीएमसी ने इसे "हर उस जागरूक नागरिक के लिए बड़ी जीत" बताया, जो चुनाव आयोग से असुविधाजनक सवाल पूछ रहा था।

पार्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा को टैग करते हुए लिखा, "भ. ाजपा के आशीर्वाद से, चुनाव आयोग ने सोचा था कि वे एसआइआर की आड़ में पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नाग. रिक रजिस्टर (एनआरसी) लाकर अपना रास्ता बना लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका देकर हकीकत से रूबरू करा दिया है।''

अब तक अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एनआरसी केवल असम में ही लागू किया गया है। भाजपा ने पूरे देश में लागू करने का वादा किया था।

भारत में लगभग 1.83 करोड़ मुसलमान हैं, जो यहां की कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 11 प्रतिशत है। ये आबादी पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड तीनों के सीमा क्षेत्र में फैले 11 समीपवर्ती जिलों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार के 11 जिलों– किशनग. ंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में रहने वाले कुल 3.39 करोड़ लोगों में से 54 प्रतिशत मुसलमान हैं जबकि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और नदिया के अलावा झारखंड में साहेबगंज और पाकुड़ मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्र हैं।

लगभग एक दशक से, भाजपा बांग्लादेश सीमा से सटे इस क्षेत्र में जनसंख्या में बढ़ती मुस्लिम हिस्सेदारी का इस्तेमाल सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए कर रही है। बंगाल के अलावा, 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भी 'घुसपैठियों' के खिलाफ जोरदार अभियान चलाए गए थे, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भाजपा के अभियान की अगुवाई की थी। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा से लगे इस क्षेत्र को निशाना बना. कर बिहार में भी इसी तरह का अभियान चलाने की उम्मीद है।

अप्रैल से विभिन्न भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी, खासकर मुसल. मानों को बड़े पैमाने पर मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने से पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा दहशत का माहौल है। टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने इस उत्पीड़न का विरोध किया, लेकिन भाजपा की बंगाल इकाई के नेताओं ने तुरंत इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया और यह जताने की कोशिश की कि कैसे टीएमसी, वामपंथी और कांग्रेस घुसपैठियों के हितों की रक्षा करने पर तुले हुए हैं। इस तरह विपक्ष बंगाल और देश के लिए घुसपैठ से जुड़े उन खतरों का बढ़ा रहे हैं, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को चेतावनी दी थी।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होगा, उससे कई राजनैतिक घटनाक्रमों के प्रभावित होने की उम्मीद है, लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और राजनैतिक चर्चाओं में नागरिकता और लोकतांत्रिक अधिकार के मुद्दे हावी रह सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग और खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में विपक्ष की वोटर यात्रा के दिन पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने उलझाऊ जवाबों के जरिए विपक्ष की शंकाओं और सवालों को घटाने के बजाए बढ़ाया ही। उन्होंने दलीलें भी गजब की पेश कीं। मसलन, मतदान के दिन की सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने पर उनका जवाब था कि माताओं–बहनों–बेटियों की इससे गोपनीयता भंग हो सकती है। यही नहीं, वे यह भी नहीं बता पाए कि बि. हार में विदेशी घुसपैठिया मिला है या नहीं। फिर, उन्होंने यह भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल ने बिना हलफनामे के शिकायतें दी हैं इसलिए उस पर कोई विचार नहीं हो पाया। अगले दिन अखिलेश यादव ने हलफनामे देने की पावती जाहिर कर दी। अगर आयोग पारदर्शी तरीके से काम करे तो शायद यह उतना बड़ा मुद्दा न बने। यही देश के लोकतंत्र के हित में है।

'आपकी इतनी हिम्मत? कार्रवाई बंद करो'

अजित पवार और महिला आईपीएस अधिकारी के बीच विवाद?

राजकुमार केशरवानी
महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख

महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एक महिला आईपीएस अधिकारी के बीच बातचीत का एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है.

मामला कथित तौर पर मुरम के अवैध खनन से जुड़ा है. वीडियो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में मौजूद माधा तहसील के एक गांव का बताया जा रहा है.

वीडियो में अजित पवार एक महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को फोन पर कार्रवाई रोकने का आदेश दे रहे हैं. अजित पवार से जब उनका पक्ष पूछा गया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की आलोचना कर रहा है.

अजित पवार ने भी इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि उनका इरादा कानून के क्रियान्वयन में हस्तक्षेप करने का नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करने का था कि उस स्थान पर स्थिति और न बिगड़े.

अजित पवार ने एक्स पर लिखा, सोलापुर जिले में पुलिस अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा इरादा कानून के पालन में हस्तक्षेप करने का नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि उस स्थान पर स्थिति शांत रहे और आगे न बिगड़े.

क्या है पूरा मामला?

रविवार (31 अगस्त) को पुलिस को सूचना मिली कि कुर्दु गांव में सड़क बनाने के लिए अवैध तरीके से मिट्टी (मुरम) निकाली जा रही हैं. इसके बाद करमाला की डीएसपी अंजना कृष्णा वी. एस. मौके पर पहुंचीं.

पुलिस अधिकारी अंजना कृष्णा ने पहले संबंधित लोगों से रॉयल्टी रसीद दिखाने को कहा. लेकिन वे ऐसी कोई रसीद नहीं दिखा पाए. इसके बाद अंजना कृष्णा ने कहा कि यह गैरकानूनी है और इसे तुरंत बंद करना होगा. इससे पुलिस अधिकारी अंजना और ग्रामीणों के बीच बहस हो गई. इस समय गांव के सरपंच और एनसीपी (अजित पवार गुट) तालुका अध्यक्ष बाबा जगताप ने सीधे उप मुख्यमंत्री अजित पवार को फोन किया.

इसके बाद बाबा जगताप ने अपना फोन अंजना कृष्णा को दिया और अजित पवार से बात करने को कहा. हालाँकि, वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा है कि अंजना कृष्णा अजित पवार को उनकी आवाज से पहचान नहीं पाईं.

वॉइस कॉल पर उनसे कहा गया, मैं उप मुख्यमंत्री अजित पवार बोल रहा हूँ. इस पर अंजना कृष्णा ने जवाब दिया, मेरे मोबाइल पर कॉल करें.

इसके बाद खुद को अजित पवार बताने वाले शख्स भड़क गए और अंजना कृष्णा को वीडियो कॉल कर डांटते हुए कहा, क्या आपकी इतनी हिम्मत है? क्या आप मेरा चेहरा भी नहीं पहचानतीं?

दावा है कि अजित पवार ने यह आदेश भी दिया, कार्रवाई रोको, तहसीलदार को बताओ कि मुझे फोन आया है.यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ग्रामीणों का दावा क्या है?

सरपंच बाबा जगताप ने कहा, कुर्दु ग्राम पंचायत के जरिए सरकारी काम हो रहे थे. ऐसे कामों में रॉयल्टी बिल से ली जाती है. लेकिन प्रशासन को गलत जानकारी देकर यह दिखाया गया कि हम अवैध खनन कर रहे हैं.

उन्होंने बताया, डीएसपी मैडम आईं और कार्रवाई शुरू कर दी. कुछ पुलिसवालों ने तो गांववालों पर जोर–जबरदस्ती भी की. तब मैंने अजित पवार को फोन किया. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई गलत है, इसे रोक दो. इसके बाद कार्रवाई रुक गई.

इस मामले में कुछ वीडियो सामने आए हैं. इनमें गांववाले आक्रामक होते और अधिकारियों को धक्का देते नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है.

विपक्ष ने साधा निशाना

शिवसेना (यूबीटी) की नेता सुषमा अंधारे ने इस घटना को लेकर फडणवीस सरक. ार की तीखी आलोचना की.

उन्होंने कहा, अगर सरकार ही गुंडों को पनाह देने वाली है, तो फिर उसमें शामिल मंत्री या विधायक से और क्या उम्मीद की जा सकती है?

सुषमा अंधारे ने आगे कहा, महिला डीएसपी ने डिप्टी सीएम अजित पवार के फोन पर गुंडों को छोड़ने से साफ इनक. ार कर दिया. दरअसल, हमें ऐसी बहादुर पुलिस अधिकारी की सराहना करनी चाहिए. सिर्फ फोन आने पर कोई महिला पुलिस अधिकारी किसी को क्यों छोड़े? यह सीधा सवाल है. चाहे वह व्यक्ति संत हो या महान आदमी, यह मुद्दा नहीं है.

उन्होंने आगे कहा, सरकार अपने विज्ञापनों में कहती है कि सीएम यानी कॉमन मैन और डीसीएम यानी डेडिकेटेड कॉमन मैन. लेकिन क्या असल में डीसीएम का मतलब डिफॉल्टर केस मैनेजमेंट है?

जनशक्ति शेतकरी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अतुल खूपसे ने कहा, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार को तुरंत महिला पुलिस अधिकारी से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए. जिस तरह महिला अधिकारी से बात की गई और फिर उन्हें डराने–धमकाने की कोशिश की गई, उसकी जांच होनी चाहिए और संबंधित लोगों पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

खूपसे ने चेतावनी दी कि अगर 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई, तो हजारों किसान सोलापुर जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर मार्च करेंगे.

आम आदमी पार्टी के विजय कुम्भार ने अजित पवार पर अवैध खनन करने वालों को समर्थन देने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, यह सब गलत है. यह सामने आया है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार अधिकारियों से अवैध कामों पर आंख मूंदने को कहते हैं. यह अधिकारी की गलती नहीं है कि उसने अजित पवार को नहीं पहचाना, क्योंकि कर्मचारी ने फोन काट दिया था.

विजय कुम्भार ने आरोप लगाया, इसी वजह से बड़े नेता चाहते हैं कि उनके इलाके में उनकी पसंद के अधिकारी तैनात हों. कुल मिलाकर, यह साबित होता है कि अजित पवार अवैध खनन में शामिल लोगों को समर्थन देते हैं.

पुलिस प्रशासन का क्या कहना है?

इस मामले में अभी तक न तो कोई शिकायत दर्ज हुई है और न ही कोई केस. डीएसपी अंजना कृष्णा, तहसीलदार और संबंधित अधिकारी ने आधिकारिक टिप्पण ी करने से परहेज किया है. प्रशासन की ओर से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जांच जारी है. कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अंजना कृष्णा की ओर से कोई जवाब नहीं मिला.

अजित पवार और बीजेपी ने क्या कहा?

पुणे में पत्रकारों ने अजित पवार से इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया पूछने की कोशिश की, लेकिन वे बिना जवाब दिए चले गए.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आनंद परांजपे ने इस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ष्कुछ मीडिया संस्थ. ान जानबूझकर यह झूठी खबर फैला रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने डीएसपी को फटकार लगाई. अस. लियत यह है कि गांव में सभी किसान तहसीलदारों की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे. तब अजित पवार ने वहां मौजूद डीएसपी अंजना कृष्णा को फोन कर का. र्रवाई रोकने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि तहसीलदारों को बता दें कि यह फोन उन्हें आया है.

आनंद परांजपे ने कहा, अगर राज्य के उप मुख्यमंत्री को डीएसपी रैंक की महिला अधिकारी नहीं पहचानती, तो यह भी गलत है. पूरा महाराष्ट्र जानता है कि अजित पवार साफ बोलते हैं और सही फैसले लेते हैं. लोकतंत्र में किसानों की बात भी सुनी जानी चाहिए. कार्रवाई रोकने का निर्देश था. लेकिन मीडिया ऐसी भ्रामक खबरें चला रहा है कि महिला अधिकारी को जानबूझकर फटकारा गया. यह गलत है. वायरल वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है.

बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, मुझे लगता है कि अजित पवार अवैध काम के लिए किसी अधिकारी को डांटने वाले मंत्री नहीं हैं. मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि सामने की स्थिति हमें मालूम नहीं होती है.

कौन हैं आईपीएस अंजना कृष्णा?

आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा का पूरा नाम अंजना कृष्णा वी. एस. है. वह इस समय महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाला में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) के पद पर तैनात हैं. पहले वह पंढरपुर में प्रशिक्षण अधिकारी थीं. अंजना कृष्णा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022–23 में पूरे भारत में 355वीं रैंक हासिल की थी.

लखनऊः पुलिस चेकिंग के दौरान कैसे पकड़ा गया फर्जी आईएएस, कई महंगी कारें बरामद

अशोक तिवारी
लखनऊ ब्यूरो प्रमुख

लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे चेकिंग कर रहे एसएचओ राकेश त्रिपाठी को अंदाजा नहीं था कि वो एक फर्जी आईएएस अधिकारी को पकड़ लेंगे. ये रूटीन चेकिंग थी. राकेश त्रिपाठी ने एक फॉर्च्यूनर कार को रोका तो पिछली सीट पर बैठे एक युवा ने अपना विजिटिंग कार्ड बढ़ा दिया.

इस पर लिखा था– डायरेक्टर आईटी, गृह मंत्रालय भारत सरकार.

राकेश त्रिपाठी बताते हैं, कार रोकने पर पीछे बैठे व्यक्ति ने भौकाल दिखाते हुए कहा कि जानते नहीं हो तुमने किसकी गाड़ी रोकी है और तुरंत विजिटिंग कार्ड थमा दिया. इस पर अशोक की लाट भी बनी थी.

आगे पुलिस पूछताछ हुई तो पता चला कि सिर्फ विजिटिंग कार्ड ही नहीं पहचान पत्र और कई अन्य दस्तावेज भी फर्जी थे. अब सौरभ त्रिपाठी नाम का ये युवा गिरफ्तार है और पुलिस उनसे जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है. सौरभ त्रिपाठी फिलहाल जेल में हैं. इस रिपोर्ट के लिए उनका या उनसे जुड़े लोगों का पक्ष नहीं मिल सका.

कई महंगी गाड़ियां बरामद

लखनऊ के डीसीपी (क्राइम) कमलेश कुमार दीक्षित ने बीबीसी को बताया, "सौरभ त्रिपाठी नाम के एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है जो कई सालों से आईएएस बनकर सचिवालयों और अन्य दफ्तरों में आ–जा रहा था."

डीसीपी कमलेश कुमार ने बताया, "अभी तक की जांच में पता चला है कि इस व्यक्ति ने कुछ साल पहले बिहार सरकार के साथ काम किया था और इसके पास सरकारी डोमेन डॉट एनआईसी की ईमेल आईडी भी थी जिसका ये दुरुपयोग कर रहा था."

पुलिस ने इस युवक के पते से डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, मर्सडीज और इनोवा जैसी छह महंगी गाड़ियां भी बरामद की हैं. हालांकि, पुलिस को अभी ये पता नहीं चला है कि जो गाड़ियां बरामद की गई हैं उनके असली मालिक सौरभ त्रिपाठी ही हैं या कोई और है.

जांच अधिकारी राकेश त्रिपाठी कहते हैं, "जो गाड़ियां बरामद की गई हैं ये अलग–अलग मालिकों के नाम पर दर्ज हैं. ये सौरभ को कैसे मिली हैं इसका पता

"

सौरभ त्रिपाठी ने अपने साथ रहने वाले लोगों से भी अपनी पूरी पहचान छुपाई थी. अभी तक की जांच में पता चला है कि वो बिहार, यूपी और उत्तराखंड में सक्रिय थे. उनके नेटवर्क में कौन-कौन हैं इसकी तलाश की जा रही है.

कमलेश कुमार दीक्षित
लखनऊ के डीसीपी (क्राइम)

लगाया जा रहा है."

पुलिस ने कई विभागों की फर्जी मुहरें, दस्तावेज, लेटरहेड और सचिवालयों के फर्जी पास भी बरामद किए हैं. पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि इस फर्जी आईएएस के पास उच्च सुरक्षा वाले इलाकों में आने–जाने के सुरक्षा पास भी थे.

आत्मविश्वास और धौंस

सौरभ त्रिपाठी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी राकेश त्रिपाठी बताते हैं कि जब उनकी गाड़ी को रोका गया था तो वो आत्मविश्वास से भरे थे और लगातार धौंस दे रहे थे.

पुलिस ने शुक्रवार को एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जो सौरभ त्रिपाठी के निजी सचिव के रूप में काम कर रहा था.

पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि प्रभाव का इस्तेमाल कर सौरभ त्रिपाठी कई कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में शामिल होते थे और अवार्ड भी बांटते थे.

राकेश त्रिपाठी बताते हैं, "जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने खुद को संयुक्त सचिव स्तर का आईएएस अधिकारी और केंद्रीय गृह मंत्रालय में कार्यरत बताया."

राकेश त्रिपाठी बताते हैं, "मैंने विजिटिंग कार्ड लेकर उस पर दिए गए ब्योरे को इंटरनेट पर चेक किया तो कुछ नहीं मिला, मुझे संदेह हुआ. जब उनसे कुछ देर रुकने के लिए कहा गया तो वो भड़क गए और कई शीर्ष अधिकारियों के नाम लेते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी."

पुलिस के मुताबिक अभियुक्त के साथ मौजूद ड्राइवर को भी बस इतना ही पता था कि वो 'बड़े आदमी हैं और आईएएस अधिकारी' हैं. डीसीपी कमलेश दीक्षित ने बताया, "सौरभ त्रिपाठी ने अपने साथ रहने वाले लोगों से भी अपनी पूरी पहचान छुपाई थी. अभी तक की जांच में पता चला है कि वो बिहार, यूपी और उत्तराखंड में सक्रिय थे. उनके नेटवर्क में कौन–कौन हैं इसकी तलाश की जा रही है."

प्रोटोकॉल, सरकारी ईमेल से लेते थे

पुलिस ने शुक्रवार को एक और शख्स को गिरफ्तार किया जो उनके ओएसडी के तौर पर काम करता था. वो डॉट एनआईसी डोमेन से ईमेल करके सौरभ त्रिपाठी को शीर्ष अधिकारी बताते हुए अलग–अलग जिलों में यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल यानी सुरक्षा लिया करते थे.

पुलिस को जांच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां भी मिली हैं. जांच अधिकारी के मुताबिक, सौरभ त्रिपाठी जब किसी सरकारी कार्यालय में जाते थे तो फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे और जब किसी कारोबारी से मिलते थे मर्सडीज कार का इस्तेमाल करते थे.

राकेश त्रिपाठी बताते हैं, "जब सौरभ को वजीरगंज थाने लाया गया तब भी उन्होंने कुछ देर धौंस जमाई लेकिन जब उन्हें अहसास हुआ कि उनका सच सामने आ गया है तो वो शहर छोड़ने का वादा करते हुए छोड़ देने की गुहार लगाते रहे."

पुलिस मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले 35 वर्षीय सौरभ त्रिपाठी के बारे में और जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रही है.

जांच अधिकारी के मुताबिक, शुरू में उन्होंने अपना पता भी गलत बताया था. जब उन्हें रोका गया तो वो सफेद शर्ट, नीली पैंट और काले जूते पहने हुए थे और किसी पेशेवर अधिकारी की तरह व्यवहार कर रहे थे.

राकेश त्रिपाठी कहते हैं, "उन्होंने खुद को संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी बताया था लेकिन उनकी उम्र कम लग रही थी, इसी से मुझे संदेह हुआ और आगे पूछताछ में पूरा सच सामने आ गया."

सौरभ त्रिपाठी अपने साथ पुलिस वर्दी में

निजी सुरक्षाकर्मी भी रखते थे. अब पुलिस ये जांच भी कर रही है कि उन्होंने ये वर्दी कहां से ली.

कैसे करते थे ठगी?

इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी के मुताबिक, सौरभ त्रिपाठी जब यूपी से बाहर जाते तो अपने आप को यूपी कैडर का शीर्ष अधिकारी बताते और जब वो यूपी में होते तो खुद को केंद्र सरकार में तैनात अधिकारी बताते.

जांच अधिकारी के मुताबिक, "सौरभ प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों का भरोसा जीतते. वो लोगों को ये बताते कि उन्हें जल्द ही यूपी में शीर्ष स्तर पर तैनाती मिलने जा रही है. अभी तक उन्होंने कितने लोगों को ठगा है ये पता नहीं चल सका है. इसकी जांच की जा रही है."

पुलिस ने सौरभ त्रिपाठी का सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाला है. एसएचओ राकेश त्रिपाठी के मुताबिक, "वह शीर्ष नेताओं, अधिकारियों और धर्म गुरुओं के साथ ली गईं तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ताकि लोगों को लगे कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं."

सौरभ त्रिपाठी ने किराए पर महंगे घर भी ले रखे थे ताकि उनसे मिलने आने वाले लोगों को उनकी कहानी सच लगे.

राकेश त्रिपाठी के मुताबिक, "उनका एक घर मऊ में है, नोएडा में गरिमा विहार में एक किराए का घर है और लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में भी एक किराये का घर है. उन्होंने ये बड़े घर किराए पर लिए ताकि अपना प्रभाव दिखाया जा सके."

डीसीपी कमलेश दीक्षित के मुताबिक सौरभ त्रिपाठी ने कंप्यूटर की पढ़ाई की है और वो आईटी क्षेत्र से जुड़े थे.

पकड़े जा चुके हैं कई ठग

ये पहली बार नहीं है जब खुद को शीर्ष अधिकारी बताने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो.

हाल ही में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया था जिन्होंने कई काल्पनिक देशों के दूतावास खोल रखे थे. उनके पास भी महंगी गाड़ियां और दुनिया के कई शीर्ष नेताओं के साथ फर्जी तस्वीरें मिलीं थीं.

पिछले सप्ताह ही राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने सड़क पर चेकिंग के दौरान पुलिस की वर्दी पहने और खुद को आईपीएस बताने वाले सुप्रियो बनर्जी को गिरफ्तार किया. उनकी गाड़ी पर नीली बत्ती भी लगी थी. पिछले महीने गुरुग्राम में फर्जी आईएएस अधिकारी जय प्रकाश पाठक को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने भी खुद को गृह मंत्रालय में कार्यरत आईएएस अधिकारी बताया था.

पुलिस जांच में पता चला वो नौकरियों और तबादले का झांसा देकर लोगों को ठग रहे थे. जय प्रकाश पाठक को इसी तरह के आरोप में इससे पहले यूपी में भी गिरफ्तार किया जा चुका था. अगस्त में ही ओडिशा के अंगुल में पुलिस ने खुद को आईपीएस बताने वाले बिरंची नायक को गिरफ्तार किया.

प्रधानमंत्री ने बिहार में एसजेवीएन की 1320 मेगावाट बक्सर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सततशील एवं औद्योगिक विकास तथा बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए पिछले 22 अगस्त को बोधगया से बिहार में 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न सीपीएसयू एसजेवीएन की 1320 मेगावाट बक्सर ताप विद्युत परियोजना की प्रथम यूनिट (1•660 मेगावाट) का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री, बिहार के उपमुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

इस कार्यक्रम में विद्युत मंत्रालय के सचिव (विद्युत), पंकज अग्रवाल और एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता, निदेशक (कार्मिक) अजय कुमार शर्मा, एसटीपीएल के सीईओ, विकास शर्मा और एसजेवीएन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। भारत और नेपाल में एसजेवीएन और इसकी अधीनस्थ कंपनियों के सभी परियोजनाओं एवं इकाइयों के कर्मी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग के साक्षी बने।

एसजेवीएन के मुताबिक,बिहार के बक्सर जिले के चौसा में स्थित 1320 मेगावाट (2•660 मेगावाट) की बक्सर ताप विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 9 मार्च 2019 को इस परियोजना की आधारशिला रखी। अत्याधुनिक सुपरक्रिटिकल तकनीक से सुसज्जित, यह परियोजना उच्च दक्षता और कम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करती है। यह परियोजना 13,756.56 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ सालाना 9,828.72 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन करेगी, जिसमें बिहार को 85ः विद्युत दीर्घकालिक विद्युत खरीद करार के तहत आवंटित की गई है।

यह परियोजना बिहार और पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी, व्यस्ततम डिमांड के दौरान विद्युत की कमी को कम करेगी और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ करेगी। इसके निर्माण में लगभग 2,54,932 मीट्रिक टन स्टील और 2,80,362 टन सीमेंट का उपयोग किया गया, जिससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के विजन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। एसजेवीएन के मुताबिक निर्माण चरण के दौरान, इस परियोजना में प्राथमिक लाभार्थी के रूप में स्थानीय निवासी के साथ प्रतिवर्ष लगभग 5,000 श्रमिक कार्यरत रहे। इस परियोजना ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार के अवसर उपन्न किए हैं, जो इसके प्रचालन चरण के दौरान भी जारी रहेंगे। इससे स्थानीय बाजारों, छोटे व्यवसायों, होटलों और परिवहन सेवाओं में भी वृद्धि दर्ज हुई, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान मिला है। इसके अतिरिक्त, एसजेवीएन ने समावेशी विकास और दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव सुनिश्चित करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पेयजल और महिला सशक्तिकरण में सामुदायिक विकास पहलों को सक्रिय रूप से आरंभ किया है।

उल्लेखनीय है कि एसजेवीएन लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में एक नवरत्न सीपीएसयू है। हिमाचल प्रदेश में भारत के सबसे बड़े 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन से अपनी यात्रा आरंभ करते हुए, एसजेवीएन के पास आज हाइड्रो, थर्मल, विंड, सौर और ट्रांसमिशन से युक्त एक विविधिकृत पोर्टफोलियो है।

SAIL लाभांश 2025: कंपनी ने

अंतिम लाभांश 2024-25 के लिए रिकॉर्ड तिथि घोषित की

भारत की सबसे बड़ी इस्पात निर्माण कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने घोषणा की है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 10 रुपये मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.60 रुपये का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है।

फाइलिंग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अंतिम लाभांश प्राप्त करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने हेतु रिकॉर्ड तिथि मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

बोर्ड द्वारा अनुशंसित वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अंतिम लाभांश, यदि आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर (टीडीएस के अधीन) भुगतान किया जाएगा।

जून तिमाही के लिए परिचालन राजस्व 8.02 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 25.92 हजार करोड़ रुपये रहा। इस बीच, वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए कंपनी की शुद्ध आय 744.58 करोड़ रुपये रही।

बोकारो स्टील प्लांट के लिए एक नया अध्याय: प्रिया रंजन ने संभाली कमान

बोकारो कृ एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन के तहत, श्री प्रिया रंजन को बोकारो स्टील प्लांट का नया प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा लिया गया यह निर्णय एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद लिया गया है, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो के 12 वरिष्ठ अधिकारियों के साक्षात्कार शामिल थे। रंजन, जो पहले सेल में कार्यकारी निदेशक (संचालन) के रूप में कार्यरत थे, इस भूमिका में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। उनकी नियुक्ति से भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन संयंत्रों में से एक, बोकारो संयंत्र के लिए विकास और परिचालन दक्षता के एक नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। पीईएसबी की सिफारिश उनके सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड और रणनीतिक दृष्टि को उजागर करती है।

यह नियुक्ति इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हुई है, जो वैश्विक बाजार में उतार–चढ़ाव और टिकाऊ एवं उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादों की बढ़ती मांग से जूझ रहा है। उद्योग जगत के जानकार रंजन की क्षमता को लेकर आशान्वित हैं कि वे संयंत्र को उसके उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने और बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ा पाएँगे।

यह नेतृत्व परिवर्तन, सेल के अपने प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। बोकारो इस्पात संयंत्र भारत के औद्योगिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बुनियादी ढाँचा, ऑटोमोटिव और निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस्पात की आपूर्ति करता है। रंजन के नेतृत्व में, हितधारकों को नवाचार, आधुनिकीकरण और कार्य बल विकास पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

आशीष कुमार ने कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (व्यवसाय विकास) का पदभार ग्रहण किया

आशीष कुमार ने कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (व्यवसाय विकास) का पदभार ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, निदेशक (विपणन) श्री मुकेश चौधरी, जो निदेशक (व्यवसाय विकास) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, 21.08.2025 से निदेशक (व्यवसाय विकास) के पद से मुक्त हो गए हैं। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है।

श्री कुमार 1994 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी (खनन) के रूप में कोल इंडिया में शामिल हुए थे। उन्होंने आईएसएम धनबाद से बी.टेक और बीआईटी मेसरा से एमबीए किया है।

इस कार्यभार से पहले, श्री कुमार भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में ओएसडी थे। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं का नेतृत्व, कोल इंडिया के महत्वपूर्ण खनिजों के विविधीकरण का नेतृत्व और भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं के निर्माण हेतु वैश्विक साझेदारियाँ स्थापित करना शामिल है।

कोयला मंत्रालय में ओएसडीध्परियोजना सलाहकार की भूमिका निभाने से पहले, श्री कुमार ने सीआईएल के महत्वपूर्ण खनिजों के विविधीकरण का नेतृत्व किया। परियोजना सलाहकार के रूप में, कोयला मंत्रालय ने नीतिगत सुधारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अमित मिश्रा ने अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार ग्रहण किया

अमित मिश्रा, आईआरएसएसई, ईडी /वी (एस एंड टी)/रेलवे बोर्ड, 20.08.2025 से अतिरिक्त प्रभार के आधार पर कॉनकॉर में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिक.

ारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए उनका कार्यकाल रहेगा।

वे भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसएसई) के 2001 बैच के हैं और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी), प्रयागराज से इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई. की डिग्री प्राप्त की है।

उन्हें उन्नत सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणालियों के संचालन और रखरखाव के साथ–साथ भारतीय रेलवे में परियोजना नियोजन, निष्पादन और अनुबंध प्रबंधन का व्यापक अनुभव है।

उन्होंने उप महाप्रबंधक और महाप्रबंधक के सचिव, तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) के रूप में प्रमुख प्रशासनिक पदों पर भी कार्य किया है, जहाँ उन्होंने नीति निर्माण, रणनीतिक योजना, निष्पादन समीक्षा और विभागों के बीच समन्वय में योगदान दिया।

श्री मिश्रा ने अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ), लखनऊ में कार्य किया है, जहाँ उन्होंने प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों, विक्रेता विकास और रेलवे सिग्नलिंग में नवाचारों में विशेषज्ञता प्राप्त की। वर्तमान में वे रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक, सतर्कता (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) हैं।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में पीईएसबी की सिफारिशों को मंजूरी दी

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने श्री रोमन सेबेस्टियन लुइस, कार्यकारी निदेशक, बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसी) को निदेशक (सेवा व्यवसाय) बीएलसी के पद पर नियुक्त करने के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए, या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रहेगी।

डॉ. हरिकृष्णन एस., कार्यकारी निदेशक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को निदेशक (संचालन), सीएसएल के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, अर्थात 31.05.2029 तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रहेगी।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अमल कुमार चक्रवर्ती को ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल) में निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त किया गया है।

एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक मानस कविराज को एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) में निदेशक (मानव संसाधन) के पद पर नियुक्त किया गया है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के महाप्रबंधक (जीएम) रमेश चंद्र महापात्रा को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में निदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, अर्थात 31.05.2029 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के कार्यकारी निदेशक राजेश गोपाल कृष्णन को सीएसएल में निदेशक (तकनीकी) के पद पर पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। पदभार ग्रहण करने की तिथि तक या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

डी. सुरेंद्रन को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का गैर–कार्यकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया

डी. सुरेंद्रन को 23 अगस्त, 2025 से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (गैर–कार्यकारी नामित निदेशक) नियुक्त किया गया है।

डी. सुरेंद्रन के पास कृषि में स्नातक, विज्ञान में स्नातकोत्तर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है। इसके अतिरिक्त, वे भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं।

उन्होंने जुलाई 1990 में केनरा बैंक में सहायक निदेशक (AEO) के रूप में अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की। अपने करियर के दौरान, वे लगातार उन्नति करते गए और 1999 में प्रबंधक, 2005 में वरिष्ठ प्रबंधक, 2008 में मुख्य प्रबंधक, 2013 में सहायक महाप्रबंधक, 2018 में उप महाप्रबंधक, 2020 में महाप्रबंधक और 2023 में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए।

बैंकिंग क्षेत्र में 35 वर्षों के अनुभव के साथ, डी. सुरेंद्रन ने विभिन्न जनसांख्यिकी क्षेत्रों में कई शाखाओं का नेतृत्व करते हुए शाखा संचालन में व्यापक विशेषज्ञता हासिल की है। उन्होंने मदुरै मंडल का नेतृत्व करके बड़ी जिम्मेदारियाँ भी संभालीं। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने भारत भर में विभिन्न स्थानों, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में काम किया है।

उन्हें मार्च 2025 से पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पंजाब नेशनल बैंक की कई समितियों में सदस्यता रखते हैं, अर्थात बोर्ड की प्रबंधन समिति, बोर्ड की आईटी रणनीति समिति, सतर्कता और गैर–सतर्कता मामलों की समीक्षा करने वाली निदेशक समिति, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति, मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति और पूंजी जुटाने वाली समिति।

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क.

Achha Kiya
INSURANCE LIYA
HEALTH | MOTOR | HOME | CROP & MORE
हार्दिक स्वागत !
NEW INDIA ASSURANCE
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd
एश्योरेंस ऑफ दि लीडर
मोटर बीमा
न्यू इंडिया महिला उधम बीमा
कोई न्यूनतम बीमा राशि आवश्यक नहीं
• न्यूनतम दस्तावेजों के साथ परेशानी मुक्त दावा निपटान
• रुपये 5 करोड़ तक की संपत्ति का जोखिम आवरण
बीमा राशि रु. 5 करोड़ तक
अतनिहित आवरण
वकल्पिक आवरण
अग्नि और संबद्ध जोखिम
लाभ की क्षति
सेंधमारी
व्यक्तिगत दुर्घटना
जन दायित्व
कर्मचारियों की व्यक्तिगत दुर्घटना
कर्मचारी मुआवजा
24x7 - Toll free number
1800-209-1415
www.newindia.co.in
@newindassurance
+91 98333 19191
Head Office: New India Assurance Bldg., 87, M.G. Road, Fort, Mumbai-400 001, INDIA
IRDAI REGN. No. 190
CIN: L66000MH1919GOI000526
Advt No.:NIA/24-25/237
All Products

भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति बना रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का मानक

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

भोपाल का यह आलीशान रानी कमल.ापति रेलवे स्टेशन इस बात का एक ताजा उदाहरण बन गया है कि किस तरह भारतीय रेलवे विश्वस्तरीय अनुभ.ाव प्रदान करने के लिए रूपान्तरित हो रहा है। रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पुन.र्विकसित यह स्टेशन भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जो सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संच.ालित किया जा रहा है।

इस स्टेशन का संचालन और रखरखाव मध्य भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों में से एक बंसल समूह द्वारा भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआ.रएसडीसी) के सहयोग से किया जाता है, लेकिन इसका स्वामित्व भारतीय रेलवे के पास ही रहता है। आईआरएसडीसी के सीईओ व एमडी एस के लोहिया सर.कार के प्रयास को क्रियान्वित कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को पुनर्निर्मित इस स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके आश्चर्यजनक बदलाव के साथ, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गोंड रानी कमलापति के सम्मान में रखा गया।

रानी कमलापति स्टेशन,यात्रियों को हवाई अड्डे जैसा अनुभव प्रदान करता है। इसकी खासियतों में -

विशाल सभा क्षेत्र और मॉडर्न वेटिंगरूम, उच्च तकनीक वाले फूड कोर्ट और खुद.रा दुकानें, सौर पैनलों के साथ पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन उन्नत सुरक्षा और निगरानी प्रणालियाँ शामिल है।

फिलहाल,रानी कमलापति स्टेशन अब भविष्य के स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए एक मानक बन गया है। सरकार नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुं.बई सीएसटी जैसे प्रमुख स्टेशनों के लिए भी इसी तरह के उन्नयन पर विचार कर रही है।

भारतीय रेलवे की गौरवशाली धरोहर अब यात्रियों को रानी कमलापति स्टेशन पर देखने को मिलेगी। धौलपुर से लाया गया नैरो गेज का ऐतिहासिक इंजन छळ स्ब्ब नं. 514 (क्ड5) पश्चिम मध्य रेलवे ने रानी कमलापति स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर संरक्षित और प्रदर्शित किया है। यह पहल न केवल रेलवे की तकनीकी विरासत को संजोने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी।

रेल आधुनिकीकरण, निर्यात के लिए आरवीएनएल और टेक्समैको ने संयुक्त उद्यम बनाया

रोलिंग स्टॉक निर्माता टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 27 अगस्त, बुध.ावार को कहा कि उसने भारत के रेलवे आधुनिकीकरण और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है।

यह उद्यम वैगन, लोकोमोटिव, कोच, ट्र.ेनसेट और मेट्रो कोच सहित माल और यात्री रोलिंग स्टॉक का निर्माण करेगा और ईपीसी परियोजनाओं, डिपो संचालन और वैश्विक निविदाओं को भी स्वीकार करेगा।

एडवेंट्ज समूह का हिस्सा टेक्समैको, 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगा, जबकि नव.रत्न सार्वजनिक उपक्रम आरवीएनएल बहुलांश शेयरधारक बना रहेगा। यह लेन–देन दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

एडवेंट्ज समूह के अध्यक्ष सरोज कुमार पोद्दार ने कहा कि यह संयुक्त उद्यम विश्व स्तरीय रेल बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के लिए भारत की क्षमता का विस्तार करेगा।

टेक्समैको के प्रबंध निदेशक सुदीप्त मुख.र्जी ने कहा,हम अगली पीढ़ी की माल ढुलाई, यात्री और मेट्रो प्रणालियाँ प्रदान

करेंगे।आरवीएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप गौड़ ने कहा कि यह सहयोग सरकार के मेक इन इंडिया और हरित गतिशीलता अभियान का समर्थन करता है। गौरतलब है कि कोलकाता स्थित टेक्समैको पश्चिम बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़ में सात विनिर्माण इका. इयाँ संचालित करती है।

आरईसी लिमिटेड की 56वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित

गुरुग्राम, 27 अगस्त 2025: आरईसी लिमिटेड की 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव ने बैठक की अध्यक्षता की और कंपनी के बोर्ड के सभी निदेशकों ने इसमें भाग लिया। कई शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे। बाद में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री श्रीवास्तव ने सभा को संबोधित किया।

उन्होंने कहा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरईसी ने रिकॉर्ड परिचालन और वित्तीय उपलब्धियाँ हासिल कीं, जिससे एक प्रदर्शन–संचालित सार्वज. निक वित्तीय संस्थान के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई। ऋण स्वीकृतियाँ ₹3,37,179 करोड़ तक पहुँच गईं, जिनमें ₹1,91,185 करोड़ का वितरण शामिल है, जो बिजली और बुनियादी ढाँचे में प्रभावी पूँजी निवेश को दर्शाता है। ऋण पुरि. तका साल– दर–साल 11% बढ़कर ₹5. 67 लाख करोड़ हो गई, जबकि निवल मूल्य 13: बढ़कर ₹77,638 करोड़ हो गया। कुल आय 19: बढ़कर ₹55,980 करोड़ हो गई, और कर–पश्चात शुद्ध लाभ 12: बढ़कर ₹15,713 करोड़ हो गया, जो ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में मजबूत विकास, मजबूत जोखिम प्रबंध् ान और रणनीतिक जुड़ाव को दर्शाता है। आरईसी में, हमारी प्रतिबद्धता केवल परियोजनाओं के वित्तपोषण तक ही सीमित नहीं हैय हम भारत के लिए एक हरित, समावेशी और सुदृढ़ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु समर्पित हैं। ईएसजी सिद्धांत हमारे हर निर्णय का मार्गदर्शन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थिरता एक अलग उद्देश्य नहीं, बल्कि हमारे नेतृत्व, निवेश और राष्ट्र पर प्रभाव का एक प्रमुख तत्व है।

इस अवसर पर, अध्यक्ष और निदेशक मंडल ने आरईसी की दूसरी स्थिरता रिपोर्ट जारी की, जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स 2021 के अनुरूप है, जो कंप. नी के पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रदर्शन को रेखांकित करती है।

राष्ट्रपति ने ONGC को प्रतिष्ठित PSUSCOPE एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया

भारत की प्रमुख ऊर्जा कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) ने एक बार फिर सामाजिक उत्तरदायित्व में अपनी अग्रणी भूमिका की पुष्टि की है। 29 अगस्त 2025 को, भारत की राष्ट्रप. ति द्रौपदी मुर्मू ने ONGC को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही की श्रेणी में प्रतिष्ठित PSUSCOPE एमिनेंस अवार्ड 2022–23 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी और लोक उद्यम विभाग के सचिव के. मोसेस चालई, आईएएस की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

यह सम्मान भारत भर में समावेशी विकास, सतत विकास और समुदायों के सशक्तिकरण के लिए छळट की अटूट प्रतिबद्धता का जश्न मनाता है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पहलों से लेकर महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, पर्यावरण ीय स्थिरता और वंचित समूहों के समर्थन तक, ONGC ने ऊर्जा अन्वेषण और उत्पादन के अपने मुख्य व्यवसाय से परे सार्थक सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए लगातार काम किया है। पि. छले कुछ वर्षों में, ओएनजीसी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है।

आईएएस अधिकारी प्रिंस धवन आरईसी लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी लिमिटेड) ने एजीएमयूटी कैडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी प्रिंस धवन को कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। अधिकारी को जल्द ही नया कार्यभार संभालने के लिए अपने वर्तमान कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के प्रबंध निदेशक और नई दिल्ली में विशेष आयुक्त (परिवहन) के रूप में कार्यरत हैं। यह नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए की गई है।

वर्तमान में, वह हार्वर्ड केनेडी स्कूल में लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय विकास में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में बीटेक और एमटेक करने के बाद, श्री धवन वर्ष 2012 में भारत सरकार में शामिल हुए। दिल्ली के विभिन्न जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य किया है।

दिल्ली सरकार में जीएसटी के विशेष आयुक्त के रूप में भी कार्यरत थे।

BHEL के AGM राजीव कुमार शर्मा की बख्तरबंद वाहन निगम में निदेशक (वित्त) के लिए चयन

सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (अनुसूची ए) में निदेशक (वित्त) के पद के लिए राजीव कुमार शर्मा की सिफा. रिश की है। यह सिफारिश मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 को आयोजित पीईएसबी की बैठक के दौरान की गई। इस पद के लिए नौ आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया।

साक्षात्कार के बाद पीईएसबी ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के अतिरिक्त महाप्रबंधक राजीव कुमार शर्मा के चयन की सिफारिश की है।

बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड, जिसे AVNL के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसकी स्थापना आयुध फैक्टरी बोर्ड के पुनर्गठन के बाद वर्ष 2021 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई के अवाडी में है। AVNL मुख्य रूप से बख्तरबंद लड़ाकू विमानों का निर्माण करती है।

रमेश चंद्र महापात्रा ने एसईसीएल के निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार संभाला

रमेश चंद्र महापात्रा ने 27 अगस्त 2025 को एसईसीएल में निदेशक (तकनी. की) का कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर, एसईसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हरीश दुहान ने श्री महापात्रा का हार्दिक स्वागत किया। एसईसीएल के निदेशक (तकनीकी) संचालन एन. फ्रैंकलिन जयकुमार और निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास ने भी श्री महापात्रा को अपनी शुभकामनाएँ दीं। एसईसीएल में शामिल होने से पहले, श्री महापात्रा ईसीएल के झांझरा क्षेत्र में क्षेत्रीय महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। भूमिगत और खुली खदानों में कोयला खनन के क्षेत्र में तीन दशकों से अधि ाक के समृद्ध और विविध अनुभव वाले एक अनुभवी खनन पेशेवर, श्री महापात्रा अपने साथ परिचालन उत्कृष्टता, रणनी. तिक दूरदर्शिता और अभिनव नेतृत्व का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आए हैं। आईआईटी–बीएचयू (खनन इंजीनियरिंग, 1990) के पूर्व छात्र, श्री महापात्रा मानव संसाधन में एमबीए भी हैं और इंस्टी. ट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के फेलो हैं।

कोचीन शिपयार्ड के निदेशक मंडल में हरिकृष्णन एस और राजेश गोपालकृष्णन शामिल

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने घोषण ाा की है कि डॉ. हरिकृष्णन एस, कार्यकारी निदेशक (जहाज निर्माण), और राजेश गोपालकृष्णन, कार्यकारी निदेशक (जहाज मरम्मत), सीएसएल ने 27 अगस्त, 2025 को कंपनी के क्रमशः निदेशक (संचालन) और निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप, कंप. नी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मधु संकुन्नी नायर, जो निदेशक (संचालन) और निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, ने क्रमशः डॉ. हरिकृष्णन एस और राजेश गोपालकृष्ण ान को यह कार्यभार सौंप दिया है। डॉ. हरिकृष्णन एस, निदेशक (संचालन) के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमबीए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट (पीएचडी) की डिग्री है। कंप. नी में लगभग तीन दशकों के अनुभव के साथ,वह हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली–सीएसएल) और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी–सीएसएल), जो सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, के निदेशक भी हैं।राजेश गोपालकृष्ण ान, निदेशक (तकनीकी) के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में विशेषज्ञता के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री है। उन्हें कंपनी में जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और रूपांतरण के क्षेत्र में लगभग तीन दशकों का अनुभव है। वह हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली–सीएसएल) और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी–सीएसएल), जो सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, के निदेशक भी हैं।

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क.

मालेगांव ब्लास्ट

साध्वी प्रज्ञा समेत सभी अभियुक्तों बरी
पीड़ित पक्ष बोला, 'हमारे साथ गलत हुआ'

श्वेतांक वर्मा
मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख

मालेगांव बम विस्फोट मामले में विशेष एनआईए अदालत ने सभी सात अभियुक्तों को बरी कर दिया है. करीब 17 साल पहले मालेगांव में हुए बम धमाकों में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे.

बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित इस मामले में सबसे चर्चित अभियुक्त रहे. साध्वी प्रज्ञा भोपाल से बीजेपी की सांसद रह चुकी हैं. 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिलों में रखे विस्फोटकों में धमाका हुआ था.

इससे पहले विशेष एनआईए न्यायाधीश एके लाहोटी ने 8 मई को सभी अभियुक्तों को 31 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था.

मुकदमे के दौरान सरकारी पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 37 अपने बयान से मुकर गए थे. बाद में इस मामले की जाँच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंप दी गई थी.

इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर, मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय राि हरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आ. ईपीसी) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

शुरुआत में इस मामले की जाँच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) कर रहा था, लेकिन 2011 में इसकी जाँच की

जिम्मेदारी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआ. ईए) को सौंप दी गई थी.

फैसला सुनाते समय न्यायाधीश ने क्या कहा?

सरकारी पक्ष यह तो साबित कर सका कि बम विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल पर ही लगाया गया था.

दावा किया गया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित कश्मीर से आरडीएक्स लेकर आए थे, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला. यह भी साबित नहीं हो सका कि पुरोहित ने अपने घर पर बम तैयार किया था.

रमजान की वजह से उस समय इलाका बंद था, और यह स्पष्ट नहीं हो सका कि मोटरसाइकिल वहाँ कैसे पहुँची.

ऐसा कहा गया कि इंदौर, उज्जैन और नासिक जैसे स्थानों पर साजिश रचने के लिए बैठकें हुई थीं, लेकिन ऐसी बैठकों का कोई विश्वसनीय प्रमाण अदालत में पेश नहीं किया जा सका.

अदालत ने यह भी पाया कि जाँच अधिकारियों ने फोन रिकॉर्ड की जांच के लिए अनुमति नहीं ली थी.

अभिनव भारत मामले में पुरोहित, राहिरकर और उपाध्याय के बीच कुछ वित्तीय लेनदेन के प्रमाण तो मिले, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि उस धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में किया गया था.

अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित करने के लिए विश्वसनीय और ठोस सबूत पेश नहीं कर सका.

सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने माना कि अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं हैं.

यह एक गंभीर अपराध था, लेकिन अदालत को फैसला सुनाने के लिए ठोस और निर्विवाद प्रमाण की आवश्यकता होती है.

सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष घोषित किया गया है.

सीएम ने क्या कहा

मालेगांव बम विस्फोट मामले में अदालत के फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है, ना कभी रहेगा!

पीड़ित पक्ष ने क्या कहा?

मालेगांव ब्लास्ट में मारी गई एक बच्ची के पिता लियाकत शेख ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, गलत हुआ हमारे साथ. उनको सजा होनी थी. हेमंत करकरे साहब ने उनको सबूत के साथ पकड़ा था. अगर उन्होंने नहीं किया तो किसने किया. उनको पकड़ना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए. अब आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. मेरी दस साल की बच्ची शहीद हुई थी. वह वड़ा पाव लाने के लिए गई थी, मैं घर में बैठा था. तभी धमाका हुआ था.

स्थानीय नेता मौलाना कयूम ने कहा, मालेगांव के लोगों को उम्मीद थी कि मुल्जिमों को सजा दी जाएगी. पीड़ित लोगों के साथ हम हाई कोर्ट का दरवा. जा खटखटाएंगे. हेमंत करकरे साहब ने जो सबूत दिए थे उसकी रोशनी में हमें उम्मीद थी कि मुजरिमों को सजा मिलेगी.

एटीएस और एनआईए जाँच में क्या अंतर था?

महाराष्ट्र एटीएस ने शुरुआत में इस मामले की जाँच की थी. एटीएस की जाँच में पाया गया था कि साध्वी प्रज्ञा की एलएमएल फ्रीडम बाइक का इस्तेमाल विस्फोटक रखने के लिए किया गया था. लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर दक्षिणपंथी समूह अभिनव भारत नामक के माध्यम से आरडीएक्स की योजना बनाने और उसे खरीदने का आरोप लगाया गया था.

जब एनआईए ने मामले की जाँच अपने हाथ में ली, तो कई आरोप वापस लिए गए. एनआईए के मुताबिक एटीएस जाँच

में कई खामियाँ पाई गईं थीं लेकिन यूएपीए की धाराएँ बरकरार रखी गईं.

मालेगांव ब्लास्ट मामला

महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक और भीकू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 29 सितंबर 2008 की रात 9.35 बजे बम धमाका हुआ था, जिसमें छह लोग मारे गए और 101 लोग घायल हुए थे.

इस धमाके में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी. एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक यह मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी.

महाराष्ट्र एटीएस ने हेमंत करकरे के नेतृत्व में इसकी जाँच की और इस नतीजे पर पहुँची कि उस मोटरसाइकिल के तार गुजरात के सूरत और अंत में प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े थे. प्रज्ञा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य रह चुकी थीं.

पुलिस ने पुणे, नासिक, भोपाल इंदौर में जाँच की. सेना के एक अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित और सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया. इसमें हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत का नाम सामने आया और साथ ही सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडेय का नाम भी आया.

मोटरसाइकिल से प्रज्ञा का कनेक्शन

एटीएस चार्जशीट के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मोटरसाइकिल उनके नाम पर होना था. इसके बाद प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया. उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) लगाया गया. चार्जशीट के मुताबिक जाँचकर्ताओं को मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के बीच एक बातचीत पकड़ में आई जिसमें मालेगांव धमाके मामले में प्रज्ञा ठाकुर की भूमिका का जिक्र था. बाद में जाँच एटीएस से लेकर एनआईए को सौंप दी गई थी. एनआईए की चार्जशीट में उनका नाम भी डाला गया.

मालेगांव ब्लास्ट की जाँच में सबसे पहले 2009 और 2011 में महाराष्ट्र एटीएस ने स्पेशल मकोका कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में 14 अभियुक्तों के नाम दर्ज किए थे. एनआईए ने जब मई 2016 में अपनी अंतिम रिपोर्ट दी, तो उसमें 10 अभियुक्तों के नाम थे.

इस चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह को दोषमुक्त बताया गया. साध्वी प्रज्ञा पर लगा मकोका हटा लिया गया और कहा गया कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ करकरे ने जो जाँच की वो असंगत थी.

इसमें लिखा गया कि जिस मोटरसाइकिल का जिक्र चार्जशीट में था वो प्रज्ञा के नाम पर थी, लेकिन मालेगांव धमाके के दो साल पहले से कलसांगरा इसे इस्तेमाल कर रहे थे.

प्रज्ञा ठाकुर को जमानत तो मिल गई लेकिन उनपर मुकदमा चलता रहा. बाद में वो 2019 में भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ीं और जीत गईं.

भोपाल से चुनाव लड़ने के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव धमाकों में लगे आरोप पर फिर सफाई दी है. उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई कुकर्म नहीं किया जो मालेगांव का भूत हमेशा उनके पीछे लगा रहेगा भोपाल को बीजेपी की मध्य प्रदेश में सबसे सुरक्षित सीटों में गिना जाता है. इस सीट पर बीजेपी साल 1989 से जीतती आ रही थी.

लेकिन जिस साल बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया था, उस बार कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को इस सीट से उतारा था. यही नहीं, इस चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी.

दो साल में दो विस्फोट

सितंबर 2008 का बम धमाका दो साल में मालेगांव में हुआ दूसरा हमला था. इससे पहले, 8 सितंबर 2006 को शब–ए–बरात के दिन वहाँ धमाके हुए थे.यह दिन मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक रूप से अहम होता है. मालेगांव की एक मस्जिद के पास चार धमाके हुए. इनमें 31 लोगों की मौत हुई और 312 लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

कब सचेत होंगे
राजनेता, मानव निर्मित पारिस्थितिक आपदाओं के प्रति ?

सुनील नेगी
उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर के विभिन्न भागों में हो रही ग्लो.बल वार्मिंग और पारिस्थितिकी आपदाओं के कारण सैकड़ों लोगों की जान जाने का खतरा वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है, जिसे केंद्र और राज्यों की सरकारों की सक्रिय भागीदारी से शीघ्रता से हल करने की आवश्यकता है, जिसमें बुद्धिजीवियों, पर्यावरणविदों, भूकंप विज्ञानियों, पृथ्वी वै.ज्ञानिकों, लेखकों, पत्रकारों, विचारकों और सबसे बढ़कर विभिन्न विचारों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया जाना चाहिए।

आप इस बात को समझेंगे कि गंगा के बढ़ते प्रदूषण,और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय की अवनति हम सबकी, पूरे देश और विश्व की है, इसलिए यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जि.म्मेदारी है कि उत्तराखंड के जंगला.ें में बड़े पैमाने पर लगने वाली आग, जो वहां की वनस्पतियों और जीवों को नष्ट कर रही है और उन्हें परेशान कर रही है, तथा वैश्विक तापमान में वृद्धि कर रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, अमित्र विकास, नदियों के किनारे रिसॉर्ट, होटल और आवासीय लक्जरी आवास का निर्माण, सभी निर्धारित सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करना और अत्यधिक बारिश और बादल फटने के दौरान अचानक आने वाली बाढ़ का आसान शिकार बनना आदि शामिल हैं, जो मानव और पशु मृत्यु का कारण बन रहे हैं और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

उत्तराखंड में बादल फटने, अत्यधिक बारिश, हिमनद झीलो, सड़क या सुरंग निर्माण गतिविधियों के दौरान जलभृतों के फटने और सड़क चौड़ीकरण गतिविधियों के दौरान डायनामाइट विस्फोट के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिससे पहले से ही कमजोर पहाड़ अंदर से खोखले हो गए हैं, जिसमें ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक भूमिगत रेलवे के लिए पहाड़ियों के अंदर 75ः सुरंगों का निर्माण और बड़े पैमाने पर लाखों पूर्ण विक.सित पेड़ों को काटना शामिल है, जिसने वास्तव में उत्तराखंड के पहाड़ों और अन्य राज्यों के पहले से ही कमजोर पर्यावरण और पारिस्थितिकी को परेशान और नष्ट कर दिया है।

बड़े पैमाने पर जम्मू और कश्मीर, किश्तवाड़ में पारिस्थितिकी विनाश, बड़े पैमाने पर मानव निर्मित प्रकृति के आक्रमण के कारण क्रोधित प्रकृति का एक और हालिया परिणाम है, जहां सैकड़ों निर्दोष लोग प्रकृति के क्रोध का शिकार हुए हैं।

अगर हम विशेष रूप से उत्तराखंड का मामला लें, तो बड़े पैमाने पर भूस्खलन और तीन हजार से अधिक गांवों के भ.ूतिया गांवों में बदल जाने के अलावा, जिसमें हाल ही में धराली, हर्षिल और थराली में हुई प्राकृतिक आपदा में कई घर, होटल, इमारतें और मानव जीवन का सफाया हो जाना शामिल है, ये सभी निकट भविष्य में होने वाले बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विनाश के स्पष्ट संकेत हैं।

उत्तराखंड हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, गौमुख ग्लेशियर भी तेजी से पिघलकर 40 किलोमीटर पीछे चला गया है, पर्यावरण के लिए सबसे प्रतिक.ूल तरीके से बनाए जा रहे सभी मौसम सड़कों के मार्गों पर भूस्खलन न1500

स्थानों पर हुआ है, जहां कई बिंदुओं पर पहाड़ी भागों सहित केदारनाथ तक का पूरा राजमार्ग पूरी तरह से बह गया है और दो हजार लोग बारिश के दौरान घंटों तक फंसे रहे हैं।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में 1,266 हिमनद झीलें हैं, जैसा कि 2015 की एक सूची में बताया गया है। इनमें से 13 को हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (ळस्व्थ्) के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। 2011–2013 के उपग्रह आंकड़ों से उत्तराखंड में 500 मीटर से अधिक आकार की 1,266 हिमनद झीलों का पता चला है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने इनमें से 13 झीलों को उच्च–जोखिम (स्तर I) के रूप में पह. चाना है और उनकी संवेदनशीलता पर आगे अध्ययन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, 16 जून 2013 को घटित हुई सर्वाधिक खतरनाक पारिस्थितिकी आपदा , जिसमें दस हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई तथा गढ़वाल और कुमाऊं के अनेक गांव उजड़ गए, ऋषि गंगा आपदा जिसमे निर्माणाधीन बाँध क्षतिग्रत हो गया और २०० लोग मारे गए , क्षतिग्रस्त हुए लगभग 200 गांवों का पुनर्निर्माण और पुनर्वास नहीं हुआ, यद्यपि तत्कालीन उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पुन. र्निर्माण और पुनर्वास किया जाएगा, के बावजूद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के आसपास हजारों करोड़ रुपए के बजट से निर्माण कार्य हुआ, जबकि लखनऊ से हमारे भूकंप वैज्ञानिकों, भूविज्ञानिया. ं आदि ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि केदारनाथ परिसर में कोई भी ठोस निर्माण न किया जाए, बल्कि भविष्य में पारिस्थितिकी आपदाओं के आने की स्थिति में होने वाले नुकसान से बचने के लिए पूरे कस्बे को उनके द्वारा चुने गए किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थान. ांतरित कर दिया जाए।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि भविष्य में ईश्वर न करे, केदारनाथ में 2013 में हुई आपदा के बराबर कोई और पर्यावरणीय आपदा आती है, तो केदारना. थ परिसर में बढ़ते निर्माण और मानवीय उपस्थिति को देखते हुए और भी अधिक विनाशकारी मुद्दे सामने आएंगे, क्योंकि हर मौसम में पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़कर लगभग 6 दृ आठ लाख हो जाती है, तथा वाहनों, चार पहिया और दो पहिया वाहनों से बेहिसाब मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जिनमें हेलीकॉप्टरों द्वारा बार–बार उड़ान भरने से ध्वनि प्रदूषण भी शामिल है, जो पर्यावरण को नष्ट और प्रदूषित करते हैं। दुर्भाग्य से उत्तराखंड आज बड़े पैमाने पर सड़क दुर्घटनाओं का भी शिकार है, जिसमें आदमखोरों के हमलों से होने वाली मौतें भी शामिल हैं।

और इसी तरह धराली, उत्तरकाशी और थराली चमोली में हिमनद फटने और बादल फटने की घटनाएं, जिनके कारण सैकड़ों मकान और इमारतें नष्ट हो गईं, मंडी, हिमाचल प्रदेश और किश्तवाड़ सहित 70 मानव मौतें हुईं, पारिस्थितिक आपदाओं में भारी विनाश और मानव मृत्यु देखी गई, जो निकट भविष्य के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक बड़ी चेतावनी संकेत भेजती है।

निष्कर्षतः, जोशीमठ में इसके धंसने, बड़े पैमाने पर प्रदूषण, ग्लेशियरों के पिघलने, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, गर्मियों के दौरान जंगलों में भीषण आग और लाखों कांवड़ यात्रियों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों द्वारा प्लास्टिक की बोतलें, पुराने कपड़े और गंदगी पीछे छोड़ जाने के कारण गंगा का अत्यधिक प्रदूषण का शिकार होना, पर्यावरणीय आपदाओं के खतरे ने हमारी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारों, विपक्षी दलों, बुद्धिजीवियों, पृथ्वी वैज्ञानिकों, पर्यावरण ाविदों आदि के लिए एक मंच पर आना और हिमालयी क्षेत्रों में वाहनों की भा. री संख्या सहित बड़े पैमाने पर बढ़ते

पैदल यात्रियों पर नियंत्रण लगाने के लिए एक विश्वसनीय नीति तैयार करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए , साथ ही पर्यावरण के लिए हानिकारक विकास पर कड़ी निगरानी और नदी के किनारे निर्माण पर कानूनी रोक लगानी चाहिए। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात यह है कि हमा. रे पास सत्तारूढ़ राजनीतिक व्यवस्था के पांच लोकसभा , ३ राज्य सभा सांसद हैं, भगवा पार्टी (भाजपा) तीसरी बार चुनी गई है, लेकिन वे संसद में उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी तबाही के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के बजाय राष्ट्रीय राजधानी में स्वागत समारोहों में भाग लेने और फूलमालाएं और गुलदस्ते स्वीकार करने में व्यस्त हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और लगातार पर्यावरणीय आपदाओं में कई गांव, सड़कें नष्ट हो गईं।

इसके अलावा इतनी बड़ी तबाही के बाद स्थिति से निपटने के लिए पिछले साल का मात्र 315 करोड़ रुपये का आवंटन और इस वर्ष छह राज्यों के लिए मात्र 1066 करोड़ भी बहुत कम लगता है।

प्रधानमंत्री की विदेशी यात्रा की सभी लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन न तो प्रधानमंत्री महोदय या एक भी केंद्रीय मंत्री ने हिमालयी राज्य के पीड़िता. ें की आहत भावनाओं पर मरहम लग. ाने के लिए आज तक उत्तराखंड के पारिस्थितिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए और हमारी मानवता को विलुप्त होने से बचाने के लिए तेजी से बिगड़ते पर्यावरण ीय स्थिति और पिघलते ग्लेशियरों को रोकने हेतु आगे आना चाहिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पूर्व महा. निदेशक, आईसीएफआरई और पर्यावरण ीय मुद्दों पर विपुल लेखन करने वाले डॉ. वी.के. बहुगुणा के अनुसार, जलवायु परिवर्तन ने मानसून की तीव्रता को बढ़ा दिया है, क्योंकि गर्म हवाएँ प्रति 1 डिग. ्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के साथ 7 प्रतिशत तक अधिक नमी धारण कर रही हैं। हिंद महासागर और अरब सागर के गर्म होने से वायुमंडलीय नमी बढ़ गई है, जिससे अचानक और तीव्र वर्षा हो रही है। हिमालयी हिमनदों के पीछे हटने और पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से पर्वतीय ढलानों में और अस्थिरता आई है, जिससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएँ बढ़ गई हैं। पहले से ही गंभीर स्थि. ति असंतुलित अनियोजित विकास और प्राकृतिक वनों और पर्यावरण के क्षरण से और भी जटिल हो गई है। अनियमित शहरीकरण, वनों की कटाई, और जल विद्युत परियोजनाओं, चल रहे चार लेन राजमार्गों, भूमिगत रेलवे, ढलानों की अनुचित कटाई और भौगोलिक परामर्श के बिना नदियों के पास और संवे. दनशील ढलानों पर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण और जल निकासी प्रणाली की अनुपस्थिति जैसी गलत अवसंरचना परियोजनाओं ने क्षेत्र की संवेदनशीलता को और खराब कर दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक आपदा, भूस्खलन, चलती गाड़ियों में पत्थर गिरने और सबसे अधिक विनाशकारी बाढ़ आ रही है। इस बीच, राष्ट्रीय हरित अध ि ाकरण ने उत्तरकाशी से गंगोत्री तक 80 किलोमीटर लंबे मार्ग पर सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में रिसॉर्ट्स, होटल और यहां तक कि आवासों के अवैध निर्माण पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। क्षेत्र में पर्यटन के बढ़ते चलन के बीच विशेषज्ञों का कहना है कि अनियंत्रित विकास इस उच्च ऊंचाई वाले तीर्थ शहर के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन रहा है और धराली त्रासदी को बड़े पैमाने पर इन अवैध निर्माणों और अनियंत्रित तथाकथित पर्यावरण विरोधी विकास आदि का परिणाम माना जा रहा है। एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून, शहरी विकास विभाग और उत्तरकाशी, गढ़वाल उत्तराखंड के जिला मजिस्ट्रेट को 27 नवंबर 2025 को जवाब के साथ एनजीटी अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा है।

लेखक -सुनील नेगी, उत्तराखंड पत्रकार मंच के अध्यक्ष है।

महाराष्ट्र के इस नए कानून को कहा जा रहा असहमति दबाने का हथियार

'महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024' पर राज्य में विवाद गहराता जा रहा है. विपक्ष ने इस कानून को अर्बन नक्सल के नाम पर विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश बताया है.

10 जुलाई को महाराष्ट्र विधानस. भा में एक ऐसा विधेयक पारित हुआ जिसे हालिया समय के सबसे विवादा. स्पद कानूनों में गिना जा रहा है. यह विधेयक वामपंथी उग्रवाद से निपटने के नाम पर लाया गया है. इसे शहरी नक्सलवाद के खिलाफ कदम बताकर सरकार ने प्रचारित किया है, लेकिन विधानसभा से लेकर सड़कों तक इसे लेकर विरोध हो रहा है.

मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का पेश किया गया महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 विधानसभा में बहुमत से पारित हुआ. अगले ही दिन यह विधान परिषद में भी पास हो गया.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिल का बचाव करते हुए कहा है कि विशेष जनसुरक्षा बिल का मकसद सरक. ार की आलोचना करने वालों पर कार्रवाई करना नहीं है. लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग अर्बन नक्सल जैसी गतिविधियों में शामिल होंगे, उन्हें इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा. विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर इसका विरोध किया. यह विधेयक अब कानून बनने के लिए राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है.

राज्य सरकार का कहना है कि यह विधेयक वामपंथी चरमपंथ या उनसे जुड़े समान संगठनों की अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है.

महाराष्ट्र ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य नहीं है. इससे पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा इस तरह के विशेष सुरक्षा कानून लागू कर चुके हैं.

विधेयक पर इतना विवाद क्यों?

बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इसे लागू करने को लेकर सख्त रुख अपना रखा है.

वहीं विपक्षी दलों, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों, आंदोलनकारियों और कई कानूनी विशेषज्ञ इसके प्रावधानों, इसकी मंशा और जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं. सत्तापक्ष पहले से यह कहता रहा है कि श्शहरी नक्सलियोंश के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग कानून की जरूरत है. 'यह शब्दावली' पुणे के भीमा कोरेग. ांव और एल्गार परिषद मामले के बाद ज्यादा उभरकर सामने आई, जिसमें कई वामपंथी विचारों से जुड़े लेखक, पत्रकार और कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए.

हालांकि कानून की मुख्य धारा में शहरी नक्सल या नक्सलवाद जैसे शब्द नहीं हैं, लेकिन विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में इसका जिक्र है.

इसमें कहा गया है, नक्सलवाद का खतरा केवल नक्सल प्रभावित दूरदराज के इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी इलाकों में भी नक्सली फ्रंटल संग. ठनों के जरिए इसकी मौजूदगी बढ़ रही है.ष सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मौजूदा कानून अपर्याप्त थे, इसलिए नया कानून लाना जरूरी था.

उन्होंने कहा, ष्छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे चार राज्यों ने ऐसे कानूनों के तहत 48 संगठनों पर बैन लगाया है. महाराष्ट्र में ऐसे 64 संगठन हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं. एक भी वामपंथी उग्रवादी संगठन पर अब तक प्रतिबंध नहीं लगा है. राज्य उनके लिए सुरक्षित शरणस्थल बन गया है.

इन अपराधों के लिए दो से सात साल तक की सजा और दो से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसमें बिना वारंट गिरफ्तारी संभव है जो गैर–जमानती है.

इस विधेयक के तहत अवैध गतिविधि की परिभाषा है – जो गतिविधि सार्व. जनिक व्यवस्था, शांति और सौहार्द को खतरे में डालेय कानून व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचे में बाधा डालेय या आप. राधिक ताकत से किसी सरकारी कर्मचा. री को भयभीत करने के इरादे से हो, वो 'अवैध' की श्रेणी में मानी जाएगी, भले ही वह लिखे गए या बोले गए शब्दों के रूप में हो.

फडणवीस ने कहा, कोई व्यक्ति केवल तब गिरफ्तार हो सकता है जब वह प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हो. अकेले व्यक्ति के खिलाफ यह कानून लागू नहीं

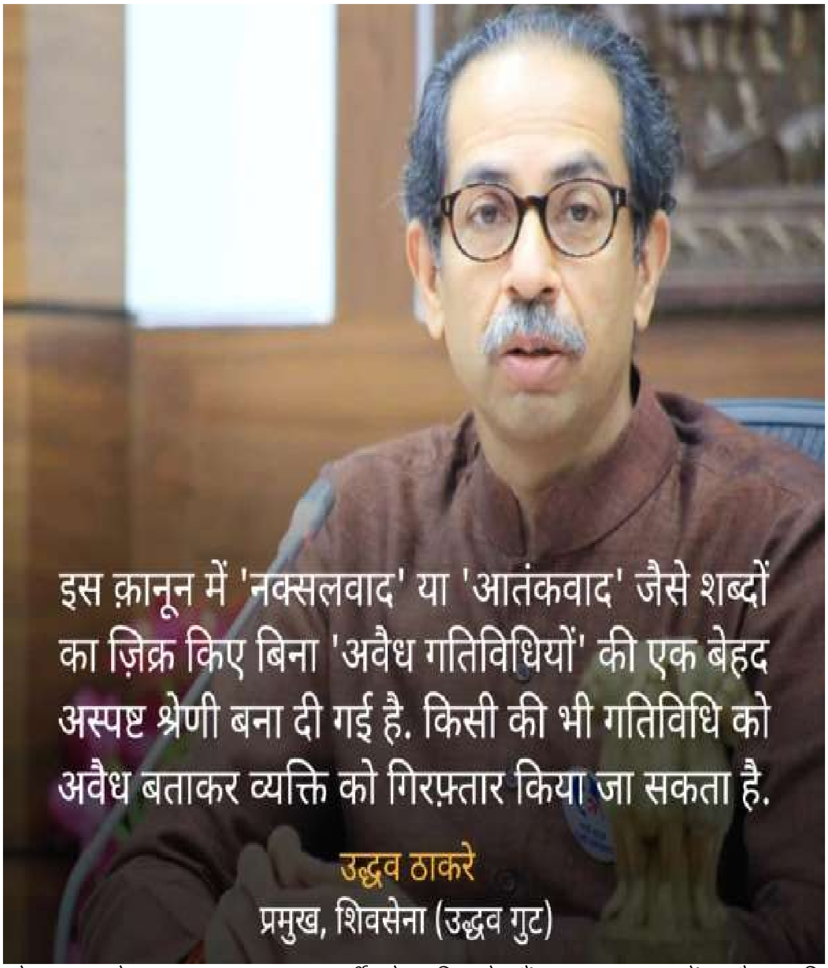

होगा. इसके तहत सरकार मनमर्जी से कार्रवाई नहीं कर सकती.

साथ ही इस कानून के तहत अगर किसी संगठन को श्अवैधश घोषित किया जाता है, तो उसे एक सलाहकार बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश करेंगे.

क्या हैं आपत्तियां?

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस कानून में कई परिभाषाएँ अस्पष्ट हैं और उनके दायरे को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है. अवैध गतिविधि की व्याख्या इतनी व्यापक है कि इसका मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है. शिवसे`ना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, ष्इस कानून में नक्सलवाद या श्आतंकवादश जैसे शब्दों का जिक्र किए बिना अवैध गतिविधियों की एक बेहद अस्पष्ट श्रेणी बना दी गई है. किसी की भी गतिविधि को अवैध बताकर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है.

द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख में राजनीतिक विश्लेषक सुहास पलशीकर लिखते हैं, नए कानून में अवैध गति. विधियों की परिभाषा है – किसी कार्य या शब्द या संकेत या दृश्य प्रस्तुति के माध्यम से किया गया कोई कृत्य. यानी बोलने की आजादी को भी अपराध की श्रेणी में लाने की मंशा है.

उनके साथ कई शिक्षाविदों और विशेष. ज्ञों ने भी इस कानून पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

पलशीकर आगे लिखते हैं, पहला खतरा यह है कि किसी भी विचारधारा या राजनीतिक विरोधी की ओर से की गई मामूली शिकायत पर भी पुलिस सक्रिय हो सकती है. दूसरा, किसी भी बौद्धिक गतिविधि को इस कानून की परिभाषा में लाया जा सकता है.

जब यूएपीए पहले से है, तो नए कानून की जरूरत क्यों?

गैर–कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) कानून पहले से मौजूद है और इसे कई संवेदनशील मामलों और कथित वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में लागू किया गया है. कई कार्यकर्ताओं पर इस कठोर कानून के तहत मुकदमा चल रहा है, जिसके तहत अपराध गैर–जमानती होता है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक, यूएपीए में किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है, यह सिर्फ व्यक्ति पर लागू होता है.

जब कुछ मामलों में यूएपीए लागू किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कोई आतंकी घटना न हुई हो. जब यह स्पष्ट हो गया कि यूएपीए पर्याप्त नहीं है, तब केंद्र ने राज्यों को ऐसा अलग कानून बनाने का सुझाव दिया. हालांकि, कई कानूनी विशेषज्ञ इस तर्क से सहमत नहीं हैं.

दूसरे राज्यों के अनुभव और उठे सवाल

बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सत्य. रंजन धर्माधिकारी ने लोकसत्ता में एक लेख में कहा है कि इस नए कानून के प्रावधान पहले से ही गैर–कानूनी गति. विधियाँ रोकथाम अधिनियमश (यूएपीए), 1967 में मौजूद हैं, जिसे बाद में कई बार संशोधित किया गया और आतंकवाद से जुड़े मामलों को भी इसमें शामिल किया गया.

धर्माधिकारी सवाल उठाते हैं कि जब यूएपीए पहले से लागू है, तो ऐसे ही उद्देश्य वाला एक और नया कानून बनाना कितना तर्कसंगत है?

उनका कहना है, अगर यूएपीए पहले से मौजूद था, तो फिर नक्सलवाद राज्यभर में कैसे फैल गया? अगर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई, तो फिर उन्हें मदद कैसे मिलती रही? कई गिरफ्तार हुए, लेकिन मुकदमा नहीं चला, इसलिए जमानत पर छूट गए. फिर भी सरकार को लगता है कि नया कानून जरूरी है.

धर्माधिकारी यह भी चेतावनी देते हैं कि अवैध गतिविधिश की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका का रुख स्पष्ट है. वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के कानून की कुछ धाराओं की व्याख्या करते हुए कहा है कि केवल किसी संगठन के प्रति सहानुभूति या सदस्यता को भागीदारी नहीं माना जा सकता.

उनके मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति और संगठन के बीच वैचारिक संबंध है, तो

उससे उसकी गतिविधियां अवैध नहीं हो जातीं. अवैध गतिविधि कुछ और ठोस रूप में सिद्ध होनी चाहिए. वरना कानून लागू नहीं हो सकता.

क्या खास वैचारिक धारा है निशाना?

कई कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि यह कानून सिर्फ वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ क्यों लाया गया है, जबकि हालिया वर्षों में कई दक्षिणपंथी या गैर–वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों की भी हिंसक गतिविधियाँ सामने आई हैं. उन्हें इस कानून के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? सामाजिक कार्यकर्ता उल्का महाजन पूछती हैं, अगर आप वामपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो दक्षिणपंथी संगठनों का क्या? गोविंद पानसरे और डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई? महाजन लंबे समय से आंदोलनों और सामाजिक संघर्षों में सक्रिय रही हैं.

सुहास पलशीकर के मुताबिक, अगर परिभाषा स्पष्ट नहीं है, तो किसी को भी वामपंथी विचारधारा का समर्थक बता. कर अभियुक्त बनाया जा सकता है. फिर पुलिस यह तय करने लाइब्रेरी–दर–ला. इब्रेरी घूमेगी कि वामपंथी विचार क्या होते हैं.

वो कहते हैं, ष्महाराष्ट्र और देश की मौजूदा सरकार को श्वामश शब्द से ही एलर्जी है. इसलिए उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वाम से उनका क्या तात्पर्य है, और किस विचार को प्रतिबंधित करना चाहते हैं.

जहां पहले से ऐसा कानून है?

राज्य सरकार का तर्क है कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही इस तरह का विशेष सुरक्षा कानून लागू किया है, इसलिए महाराष्ट्र में भी इसकी जरूरत है. लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे इन राज्यों में कानून के दुरुपयोग के उदाहरण दे रहे हैं.

बिलासपुर हाई कोर्ट में मानवाधिकार वकील शालिनी गेरा कहती हैं, हमा. रे अनुभव में, खासकर बस्तर में, यह कानून सरकार द्वारा किसी को भी निशाना बनाने के लिए मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया गया है.वह बताती हैं, को. विड–19 के दौरान साल 2021 में मूलव. ासी बचाओ मंच नाम की एक युवा संस्था बनी थी, जो सेना के कैंप और खनन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी. लेकिन अक्टूबर 2023 में अचानक इस संगठन पर इस कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया. उनसे जुड़े कई लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया.

शालिनी गेरा कहती हैं, सरकारी नो. टिफिकेशन में कहा गया कि वे सरकार की विकास नीतियों का विरोध कर रहे थे, लेकिन कहीं भी हिंसक गतिविधि का जिक्र नहीं था. शालिनी कहती हैं कि इस कानून में कानूनी सुरक्षा बहुत सीमित है. वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गवांडे बताते हैं, ष्छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ पत्रकारों पर भी इस कानून का इस्तेमाल किया.

जो पत्रकार बस्तर जैसे क्षेत्रों में रिपा. ेर्ट करते हैं, उनका जमीनी संपर्क होना लाजमी है. लेकिन इस आधार पर कार्रवाई करना इस कानून का दुरुपयोग था. तेलंगाना में भी 2021 में 16 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन आला. ेचना के चलते तीन महीने बाद इसे वापस ले लिया गया.

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, महागठबंधन के लिए सत्ता की चाबी?

शक्ति प्रकाश
बिहार ब्यूरो प्रमुख

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पटना के डाकबंगला चौराहे पर बीजेपी को चेतावनी भरे अंदाज में कहा, महादेवपुरा के एटम बम के बाद बिहार में हाइड्रोजन बम आने वाला है.

इससे ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के मुद्दे को यहीं छोड़ने वाली नहीं है बल्कि अभी इस मुद्दे के इर्द गिर्द और भी कार्यक्रम भविष्य में बुने जाएंगे.

लेकिन फिलहाल वोटर अधिकार यात्रा के खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में तैर रहा है, वो ये कि इस यात्रा का महागठबंधन के लिए हासिल क्या है?

बीते विधानसभा चुनाव में कमजोर कड़ी साबित हुई कांग्रेस क्या अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत कर पाएगी? और क्या तेजस्वी यादव अपनी छवि को री–इनवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं?

वोटर अधिकार यात्रा: 17 अगस्त से 1 सितंबर

बीते 17 अगस्त को रोहतास जिले में राहुल गांधी की यात्रा जिस तरह की चिलचिलाती गर्मी में शुरू हुई थी, लगभग उसी तरह के मौसम में आज यात्रा का समापन भी हुआ. गर्मी परवान पर थी लेकिन इससे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जुटे समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा नहीं हुआ.

पूरे गांधी मैदान में बिखरे हुए समर्थक अपने अपने झंडों के साथ थे और गांधी मैदान के बाहर भी सड़कों पर उनका हुजूम था.

पेड़ की छांव में बैठे हुए आरा से आए जमुना कहते हैं, राहुल जी बहुत दिन बिहार रह गए. वो चले जाएंगे, इसलिए उनको विदा करने अपनी मजदूरी छोड़कर आए हैं.

राहुल गांधी इस वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम के तहत बिहार में 15 दिन रहे. राज्य के 25 जिले में 1300 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने अपने महागठबंधन के सहयोगियों के साथ की.

इस पूरी यात्रा में उनके साथ खुली जीप में राजद नेता तेजस्वी यादव, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी के मुकेश सहनी रहे.

पटना सिटी से आईं नसरीन बानो कहती हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़ तो आप सुन ही रही हैं. हमारे वोट के अधिकार की ही लड़ाई चल रही है. उसी के लिए हम लोग यहां आए हैं. गर्मी बहुत है लेकिन अभी आफत वोट पर है.

इन यात्राओं में सभी दल एक तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रहे हैं. राजद, कांग्रेस, वीआईपी, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम के साथ साथ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के झंडे इस पूरी यात्रा में दिखे.

कांग्रेस के लिए संजीवनी?

इस पूरी यात्रा में फ्रंट सीट पर राहुल गांधी रहे लेकिन इसके चलते महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में किसी तरह की दरार नहीं दिखी. बल्कि नेतृत्व के स्तर पर भी बेहतर तालमेल दिखा.

तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को बहुत सहजता से स्पेस दिया और कन्हैया–पप्पू यादव के साथ सहज दिखे. इसी के चलते लोजपा (आर) प्रमुख चिराग पासवान ने

तेजस्वी को कांग्रेस का पिछलग्गू कहा.

राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र कहते हैं, चूंकि महागठबंधन के भीतर एक चीज तय है कि अगर उसकी जीत हुई तो तेज. स्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे. इसलिए महागठबंधन के सबसे बड़े दल राजद और उसके नेता तेजस्वी को कांग्रेस में कोई खतरा महसूस नहीं होता.

उन्होंने कहा, ये भी ध्यान रखना होगा कि चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रही है उसमें 1 फीसदी वोटरों के नाम हटाए जाने का मतलब महागठबंधन के 3 से 4 फीसदी वोटर्स का नुकसान है. इसलिए महागठबंधन के दलों के भीतर भी वोट ट्रांसफर एक जरूरी प्रक्रिया है और इसके लिए जरूरी है कि उनमें एकता दिखे. इस यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं.

सुपौल से आए कांग्रेसी कार्यकर्ता महेश मिश्र कहते हैं, कुछ लोगों को भ्रम था कि कांग्रेस की जमीन गिरवी हो गई है. लेकिन इस यात्रा ने दिखा दिया कि कांग्रेस का जमीन और जमीर लौट चुका है.

लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा कितना मजबूत होगा?

कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन कहते हैं, वोटर अधिकार यात्रा से पहले राहुल गांधी पांच बार बिहार आए सामाजिक न्याय की बात की. पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित, आदिवासी और आर्थिक वंचित समाज के लोगों को मुख्यधारा में लाने और आर्थिक–शैक्षणिक न्याय देने की बात बार बार दोहरा रहे हैं.

उन्होंने कहा, ष्इसी का नतीजा है कि बीते कुछ महीनों में कानू, बिंद, नोनिया, केवट, माली, वैश्य, बुनकर, पासवान, रविदास आदि समाज के लोगों ने बड़ी तादाद में कांग्रेस ज्वाइन किया और उनकी भागीदारी इस पूरी यात्रा में दिखती है.

उन्होंने दावा किया, हमारा संगठन मजबूत होने जा रहा है. इस यात्रा में हम घर घर तक पहुंच गए हैं और ये हमारे लिए संजीवनी का काम करेगी.

लेकिन नवंबर 2017 के बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं बनी है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इसके गठन

"

2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी...इसका असर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पड़ा. लेकिन हमने विनम्रता से स्वीकार किया. इन लोगों के लिए उस समय चुनाव आयोग तो ठीक था, अब चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं.

रविशंकर प्रसाद

बीजेपी के वरिष्ठ नेता

की उम्मीद भी नहीं है.

कन्फ्यूजन की स्थिति

आम मतदाताओं के बीच अपने वोट को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति है और इसी सवाल को इस वोटर अधिकार यात्रा ने स्वर दिया है.

पटना के गांधी मैदान में चाय बेचने वाले भजन राय कहते हैं, ष्नरेंद्र मोदी 15 साल से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, नीतीश कुमार भी बन रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही, ये हम नहीं जानते. लेकिन ये लोग लगातार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं.

वहीं लखीसराय की संजू देवी कहती हैं, ये जो कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं. इसलिए गरीब गुरबा का नेता नहीं जीतता है.

महागठबंधन ने बिहार में जब ये यात्रा शुरू की तो सारा जोर एसआईआर पर ही था लेकिन धीरे धीरे इस यात्रा को राशन, दवाई, पढ़ाई, पेपर लीक, रोजगार आदि मुद्दों से भी जोड़ा गया.

इस यात्रा में कई लोग मिले जो अपनी इन मांगों के साथ आए थे. खुद राहुल गांधी ने नए पोस्टर जारी करके इन सभी मुद्दों को एसआईआर से जोड़ा.

पटना के गांधी मैदान में नवादा से आई रजिया देवी कहती हैं, हमको जमीन का कागज नहीं मिल रहा है. राशन पांच किलो मिलना चाहिए तो चार किलो मिलता है. क्या भूखे ही वोट देंगे? और हमारा वोट लेकर नेता चला जाएगा?

वहीं जुर चौपाल कहते हैं, हम लोगों का वोट नहीं रहेगा तो कोई अधिकार नहीं मिलेगा. अभी कह रहा है आधार कार्ड दिखाओ, दूसरे कागज दिखाओ, जिसके पास कागज नहीं होगा, वो क्या करेगा?

बीजेपी का क्या कहना है

वोटर अधिकार यात्रा के जरिए महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन को एनडीए ने फ्लॉप बताया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी. इसका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में असर पड़ा. लेकिन हमने चुनाव आयोग पर कुछ नहीं कहा.इन लोगों के लिए उस समय चुनाव आयोग तो ठीक था, अब चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं. लेकिन देश की जनता को जब ये सच्चाई पता चली तो उसने उन्हें हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बुरी तरह हराने का काम किया... अब बिहार में भी हराएंगे.

बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान कहती हैं, महागठबंधन अपनी इज्जत बचाने की कोशिश और राहुल गांधी अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में बार बार बिहार आ रहे हैं.

उन्होंने कहा, हम लोग यानी एनडीए के सभी दल लोगों तक केंद्र और राज्य की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में लगे हैं और आचार संहिता से पहले सारे अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. जनता जानती है हम काम करने वाले हैं और महागठबंधन हल्ला और अपमान करने वाला.

वहीं जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है, ष्वोटर अधिकार यात्रा चुनावी नौटंकी है. हार की आहट से ये यात्रा उपजी है जो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई है. वोट चोरी तो राजद के जमाने में होती है हमारी सरकार ने तो मानव विकास और आधारभूत संरचना को लेकर काम किया है.

महागठबंधन के लिए इस यात्रा का हासिल क्या है?

राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं, पहले महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के दिमाग मिले थे. इस यात्रा के बाद उनका दिल और दिमाग दोनों मिल गया है. आप अंदाजा लगाएं जब जमीनी स्तर पर दिमाग और दिल मिल जाएं तो चुनाव के परिणाम क्या आने वाले हैं.

NBCC
A Navratna CPSE

BHARAT MANDAPAM

A Landmark in Sustainability

Proudly Honored with **GRIHA 4-Star Rating** for Green Excellence

NBCC (India) Ltd. proudly celebrates the GRIHA 4-Star rating for Bharat Mandapam, recognizing it as a model of sustainable development. This state-of-the-art facility at Pragati Maidan reflects our unwavering commitment to eco-friendly innovation, seamlessly combining modern design with environmental responsibility to shape India's green future.

The award celebrates the project's excellence in adhering to 31 sustainability criteria, reducing energy consumption, promoting renewable energy, and fostering a greener urban landscape.

Sustainability Milestones at Bharat Mandapam

Energy Efficiency: 43.5% reduction in energy consumption through efficient air-conditioning, LED lighting, and star-rated equipments.

Water Conservation: 70% annual water savings with a 1.1 MLD STP and low-flow fixtures.

Smart Monitoring: Advanced Building Management Systems (BMS) for efficient resource utilization.

Biodiversity Preservation: Retention of 800+ mature trees and plantation of 5,000 native trees.

Waste Management: On-site treatment of organic waste with an Organic Waste Converter (OWC).

Urban Greening: Over 20,000 plants added to Delhi's landscape, enhancing air quality and aesthetics.

Renewable Energy: 25% reduction in grid dependency with 400 KWp solar PV installations.

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NBCC (INDIA) LIMITED
(A Government of India Enterprise)

स्मृति इरानी के शो

‘क्योंकि सास भी कभी..’ की टीवी पर वापसी

संजय सिन्हा
हरियाणा ब्यूरो प्रमुख

‘घर घर की रानी, तुलसी विरानी’– साल 2004 में जब अभिनेत्री स्मृति इरानी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब उस समय की चुनावी सभाएँ इन नारों से सजी होती थीं.

लोग उन्हें स्मृति इरानी नहीं, तुलसी विरानी के रूप में पहचानते थे. बहू के रूप में तुलसी विरानी यानी स्मृति इरानी टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सबसे मशहूर किरदारों में से एक थीं.

आज की पीढ़ी स्मृति इरानी को भाजपा नेता, सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री के तौर पर जानती है. उन्हें तीखी राजनीतिक बहसों में बोलते हुए सुना है, राहुल गांधी के खिलाफ पलटवार करते देखा है.

यह वह दौर था जब भारत के कस्बों, शहरों में हिंदी सीरियल देखने वाले लोग रात को 10.30 बजे कामकाज निपटा, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ देखने के लिए जुटते थे. इसे देखना एक तरह का पारिवारिक, सामूहिक उपक्रम था.

अब करीब 25 साल बाद, दर्शकों ने स्मृति इरानी जैसे कुछ पुराने चेहरों और कई नए चेहरों के साथ टीवी सेट पर ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी– सीजन 2’ देखा है.

तुलसी जैसी बहू हो जो बड़ों की हर बात माने

एक ओर जहाँ इस सीरियल ने कामयाबी की नई इबारतें लिखीं, वहीं इसकी आलोचना भी होती रही है कि औरतों के मामलों में इस शो ने पिछड़ी सोच को पर्दे पर लाने का ट्रेंड शुरू किया. वैसे भारत के बाहर भी यह सीरियल बहुत मशहूर रहा है. वह भी बिना किसी सोशल मीडिया के.

सॉफ्ट पावर ऑफ इंडियन टेलीविजन शोज इन नेपाल नाम के शोध पत्र में डंबर राज भट्टा ने लिखा है, सीरियल का असर यह था कि नेपाल में शहरी औरतें कहती थीं कि उन्हें तुलसी जैसी बहू चाहिए. मेरी एक रिश्तेदार ने कहा था कि तुलसी जैसी बहू हो जो बड़ों की हर बात माने.

दारी भाषा में डब होकर अफगानिस्तान में प्रसारित होने वाला यह पहला भारतीय सी. रियल बना. वहाँ यह तुलसी नाम से मशहूर था. वहाँ यह किस्सा मशहूर था कि जब लोग तुलसी देख रहे होते थे, चोर ठीक उसी समय चोरी करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि लोग टीवी पर टकटकी लगाए बैठे होंगे. हालांकि अफगान संस्कृति के हिसाब से कई सीन धुँधले कर दिए जाते थे– जैसे औरतों के कपड़े या नाचन गाने के सीन या धार्मिक चिह्न. भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल कई जगह इस सीरियल का क्रेज था.

प्रोग्रेसिव दावे गलत

यूँ तो नए सीजन के अभी कुछ ही एपिसोड आए हैं, जिनमें जेन जी है, सोशल मीडिया पर हैशटैग डालते और सेल्फी अपलोड करते किरदार हैं. लेकिन बातें कुछ वही पुरानी सी लगीं.

जैसे जब तुलसी अपनी बहू से कहती – घर में माँ, बहू, बेटी अगर खाना बनाए और खाने की महक पूरे घर में जाए तभी घर, घर जैसा लगता है. या जब तुलसी बच्चों से कहती है, “मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा. ये घर ऐसे ही चलता है.”

पुराने सीरियल की अप्रत्याशित सफलता के बावजूद यह सवाल अब भी बरकरार है कि इस सीरियल ने क्या वाकई औरतों के मुद्दों को प्रोग्रेसिव तरीके से दिखाया.

कुछ दिन पहले एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, ष्एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने शोध में पाया था कि इस शो ने भारतीय घरों में औरतों को एक नई आवाज दी. साल 2000 और 2005 के बीच पहली बार औरतें पारिवारिक चर्चाओं का हिस्सा बनने लगीं. ये बदलाव काफी हद तक भारतीय टीवी से प्रभावित था, खासकर श्क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ और ‘कहानी घर घर की’

पेमराज सारदा कॉलेज की प्रोफेसर माधुरी टीवी और फिल्म जगत पर क्रिटिकल टिप्पणियाँ भी लिखती हैं. वह कहती हैं, इन धारावाहिकों में औरतों के मुद्दों को बहुत सजा–संवारकर सतही तौर पर परोसा गया. आप देखिए टीवी सीरियल में औरतों को कितने समझौते करने पड़ते हैं. सीरियल का अंत भले कैसा भी हो, परिवार का पुरुष प्रधान सिस्टम जस का तस ही रहता है. इसलिए इन टीवी सीरियलों द्वारा औरतों के मुद्दों को उठाने का श्रेय लेना ठीक नहीं होगा.

रजनी, शांति, उड़ान जैसे भी सीरियल

यहाँ हम एकता कपूर के बयान पर लौटते हैं कि इस शो ने भारतीय घरों में औरतों को एक नई आवाज दी. अगर साल 2000 से पहले के हिंदी टीवी धारावाहिकों पर नजर डालें तो 1985 में दूरदर्शन पर सीरियल श्रजनीश आया था जिसमें एक आम महिला (प्रिया तेंदुलकर) सरकारी महकमे के लचर और भ्रष्ट रवैये के खिलाफ आवाज उठाने वाली नागरिक बनती है.

साड़ी पहने और बड़ी सी बिंदी लगाने वाली ‘रजनी’ एक एपिसोड में एलपीजी सिलेंडर के दाम में गैर–कानूनी बढ़ोतरी के खिलाफ डिलीवरी एजेंटों के विरोध में खड़ी हो जाती है.इसका इतना असर हुआ था कि ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स शो के खिलाफ प्रदर्शन करने आ गए थे.

साल 1989 में दूरदर्शन पर ही श्उड़ानश नाम का सीरियल आया था जो भारत की पहली महिला डीजीपी पर आधारित था.
90 के दशक में लोगों ने सीरियल शांति में मंदिरा बेदी को एक बेबाक, आजाद खयाल महिला जर्नलिस्ट के रूप में देखा गया जो कामकाजी है, और अपने लिए लड़ना जानती है. इसलिए यह कहना कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल पहली दफा औरतों की आवाज बने यह पूरी तरह वाजिब नहीं लगता.

उठाए मैरिटल रेप जैसे मुद्दे

वहीं कई समीक्षक और इंडस्ट्री के लोग इस सीरियल और एकता कपूर के पक्ष में खड़े नजर आते हैं. रोहिणी निनावे टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हैं और पिछले 28 सालों से कई टीवी सीरियल लिख चुकी हैं. उनका नजरिया है, मैं नहीं कहूँगी कि ये रिग्रेसिव कहानी थी. शो में कोशिश की गई थी कि औरतों को उनके हक, अपने अस्तित्व का एहसास दिलाया जाए. उस वक्त के हिसाब से सीरियल में बा से लेकर बहू तक के किरदारों को अच्छे से दिखाया गया था.
यह वह वक्त था जब औरतें अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रही थीं. लेकिन गाँव—कस्बों में औरतों की स्थिति अलग थी और है. औरतों को यही सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करो, घर का काम करो. औरतें रिश्तों में ही उलझी रहती हैं, तो सीरियल में भी यही दिखाया गया.
वहीं लेखिका लक्ष्मी यादव मानती हैं कि जो औरतें अपनी दहलीज लाँघकर अपनी नई पहचान बनाना चाहती थीं, उनको फिर से दहलीज के अंदर लाने का काम इस धारावाहिक ने अप्रत्यक्ष रूप से किया. लक्ष्मी यादव के मुताबिक, परिवार भी यह सीरियल देखकर घर की औरतों से उसी निस्वार्थी रूप की परंपरावादी उम्मीदें रखने लगा. इस धारावाहिक ने भारत की औरतों को सिर्फ दो तरह की औरतों में बांटा, देवी तुलसी और डायन मंदिरा.
स्मृति इरानी भी लगातार आलोचनाओं को खारिज करती रही हैं.
क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वापसी पर स्मृति इरानी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, ष्इस शो ने भारतीय घरों में कई मुश्किल मुद्दों पर आवाज उठाई. जब मेनस्ट्रीम मीडिया में यह हिम्मत नहीं थी, उससे पहले इस शो ने जटिल सामाजिक सच्चाइयों से रूबरू करवाया.
‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में एक प्लॉट मैरिटल रेप पर आधारित था, जहाँ सास बन जाने पर तुलसी अपनी बहू के लिए लड़ती है, जो मैरिटल रेप का शिकार होती है. इस सीरियल में बा यानी दादी को फैशन डिजाइन स्कूल में जाते दिखाया गया है और ‘एडल्ट लिटरेसी’ जैसा मुद्दा दर्शाया है.

पुरुष लीड से ज़्यादा पैसे

स्मृति इरानी ने करण जौहर के साथ शो में एक और बात उठाई. उन्होंने बताया कि इस धारावाहिक ने दूसरे मायनों में भी ग्लास सी. लिंग की क्योंकि बतौर महिला किरदार उन्हें मेल लीड के मुकाबले ज़्यादा फीस मिलने लगी जो नहीं होता था.
सोशल मीडिया पर नजर डालें तो वहाँ भी ये बंटी हुई राय देखी जा सकती है. सोशल मी. डिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुंदर राय लिखते हैं— संभ्यता, संस्कृति और संस्कार की झलक लिए मेरी माँ की फेवरिट तुलसी बहू आ रही है लेकर, हमारे घर अपना परिवार. माँ तो नहीं रही लेकिन पूरी दुनिया कर रही है इंतजार.

जेन जी की कसौटी पर खरी उतरेंगी स्मृति इरानी?

जब ‘क्योंकि सास भी कभी बहू’ 2000 में आया था तो थिएटर जाने के अलावा टीवी ही मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया था. ओटीटी, सोशल मीडिया नहीं था.
लोगों ने विदेशों का कॉन्टेंट बहुत नहीं देखा था. यह सीरियल परिवार को साथ लाकर बिठाने का भी एक माध्यम था. लेकिन आज हर मेंबर अपनी पसंद के हिसाब से अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर कुछ भी देख सकता है. रिश्तों, शादी को लेकर जेन जी की मान्यताएँ अलग हैं. तुलसी बहू के हर पहलू, हर कदम, हर त्याग, हर रस्मो रिवाज को आदर्श की तरह स्वीकार लेने वाली पीढ़ी से आगे, स्मृति इरानी अब 25 साल बाद जेन जी की कसौटी पर खरा उतर पाएगी?
जब 2000 में एकता कपूर ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ लेकर आई थी, तो उस समय के पोस्ट लिबरलाइजेशन वाले भारत में बहुत से लोगों ने इसे एक नए प्रयोग के तौर पर देखा— किसी ने इस प्रयोग को सही माना और प्रोग्रेसिव माना और किसी ने दकियानूसी. लेकिन कुछ नया और एक्सपेरिमेंटल लाने की बजाय जब 25 साल पहले के हिट सीरियल को ठोक पीटकर दोबारा परोसा जाए तो सवाल यह भी उठता है कि क्या टीवी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डिफेंसिव मोड में चली गई, जहाँ कुछ नया करना या कहना रिस्की हो सकता है? टीवी लेखिका रोहिणी निनावे मानती हैं, यह शो बिजनेस है और ऐसे पेंतरे आजमाने पड़ते हैं.

जब भारत ने ओलंपिक खेलों में आखिरी बार जीता हॉकी का स्वर्ण पदक

बात वर्ष 1980 की है. भारतीय हॉकी टीम मॉस्को ओलंपिक की तैयारी कर रही थी. टीम को बंगलौर में ट्रेनिंग दी जा रही थी. ट्रेनिंग के दौरान 1971 की लड़ाई के हीरो फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने आकर टीम का जोश बढ़ाया था.

यही नहीं, इसके बाद दो पूर्व हॉकी लीजेंड्स लेजली क्लॉडियस और एम राजगोपाल ने आकर उन्हें अपने स्वर्ण पदक जीतने की कहानी भी सुनाई थी.

ये टीम जब मॉस्को के लिए रवाना हुई, तो उससे कोई बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थीं. एक तो 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में वो सिर्फ सातवाँ स्थान प्राप्त कर पाए थे और दूसरे इस टीम के सिर्फ पाँच खिलाड़ियों को ही अंतरराष्ट्रीय मैच खेल. ने का अनुभव था.

सन 1980 के ओलंपिक खेलों में सिर्फ छह देशों ने भाग लिया था. कई पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान में सोवियत सेना भेजे जाने के विरोध में मॉस्को ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया था.

पहले मैच में आसान जीत

मॉस्को के मौसम और प्लेइंग कंडिशन्स को समझने के लिए हॉकी टीम को ओलंपिक दल से 12 दिन पहले मॉस्को भेजा गया.

इसकी एक वजह ये भी थी कि मॉस्को ओलंपिक में पहली बार पॉली ग्रास का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर खेलने के भारतीय खिलाड़ी अभ्यस्त नहीं थे. भारत ने टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत करते हुए तंजानिया को 18–0 से हराया.

वरिष्ठ खेल पत्रकार के दत्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया के 21 जुलाई, 1980 के अंक में लिखा था, इस जीत ने भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी. डायनामो स्टेडियम में खेला गया मैच पूरी तरह एकतरफा था और भारतीय टीम को अपनी कमियाँ जाँचने का कोई मौका नहीं मिला.

मैच देख रहे बलबीर सिंह सीनियर ने भी कहा था, पहले ही मैच में इतना अच्छा स्कोर भारतीय टीम और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए काफी था.

पोलैंड से आखिरी सेकेंड में हुआ मैच बराबर

दूसरे मैच में भारत की टक्कर हुई पोलैंड की टीम से. अंतिम क्षणों तक भारत की टीम पोलैंड से 1–2 से पीछे थी.

बिल्कुल आखिरी सेकेंड में मर्विन फनां. डिस ने गोल दागकर भारत की आशाओं को जगाए रखा. इस मैच में भारतीय टीम डच अंपायर बॉब डेविडसन के कई फैसलों से खुश नहीं थी.

पेनल्टी कॉर्नर से गोल न कर पाने के लिए उन्होंने अंपायर को दोषी ठहराया.

उस टीम में भारतीय टीम के लेफ्ट आउट जफर इकबाल ने बीबीसी को बताया था, इस मैच में हमारे पसीने छूट गए. पोलैंड ने मैन टू मैन मार्किंग कर रखी थी और हम लोग इसके आदी नहीं थे. इससे पहले भी पिछले 20–30 सालों में जब भी पोलैंड से हमारा मुकाबला हुआ था. हमारे लिए उनको हराना कभी आसान नहीं रहा था.

भारत का तीसरा मैच स्पेन से था. इस मैच में भी भारत ने आखिरी क्षणों में गोल मारकर अपनी उम्मीदें बनाए रखीं. इस मैच में भी भारतीय टीम अंपायर के फै. सलों से खुश नहीं दिखी, लेकिन उसने उनके खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत नहीं की.

बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता ने अपनी किताब ओलंपिक्स द इंडियन स्टोरी में लिखा है, मॉस्को भेजी गई भारतीय हॉकी टीम सबसे शक्तिशाली टीम भले ही न रही हो, लेकिन शारीरिक फिटनेस के क्षेत्र में ये टीम कई भारतीय टीमों से बेहतर थी.

अगले मैच में भारत ने कमजोर क्यूबा की टीम को 13–0 से हराया. इसके बाद भारतीय टीम का मुकाबला मेजबान सोवियत संघ की टीम से था.

भारत ने ये मैच देवेंदर सिंह के दो गोलों की बदौलत 4–2 से जीता. लेकिन ये मुकाबला इतना आसान नहीं था, जितना स्कोरबोर्ड बता रहा था. इस मैच में अंपायर भारतीय टीम पर मेहरबान रहे और सोवियत खिलाड़ी अंपायरिंग से खुश नहीं दिखाई दिए.

के दत्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया के 26 जुलाई, 1980 के अंक में लिखा, रूसियों ने भारत से बेहतर गति दिखाई. हाँ, उनका गेंद पर नियंत्रण भारत से कमजोर था. कई बार वो फ्लैंक्स से भारतीय क्षेत्र में घुसे और गोलकीपर छेत्री को उन्होंने कभी चैन से नहीं बैठने दिया.

टीम के कप्तान भास्करन ने बीबीसी को बताया था, इस टूर्नामेंट में पहली बार हमने मैच से पहले वीडियो पर रात भर सोवियत खिलाड़ियों के खेल को देखा और अपनी रणनीति बनाई. हमने तय किया कि देवेंदर सिंह डायरेक्ट पेनल्टी कॉर्नर न लेकर इनडायरेक्ट पेनल्टी कॉर्नर लेंगे. रूसी हमसे इस तरह की रणनीति की उम्मीद नहीं कर रहे थे और वो इसके लिए तैयार भी नहीं थे.

फाइनल में स्पेन पर शुरुआती बढ़त

भारत का फाइनल मैच स्पेन से था. स्पेन उस वर्ष का यूरोपियन चौंपियन था और उसकी पेनल्टी कॉर्नर से गोल करने की क्षमता भारत से बेहतर थी. भारत की अपेक्षाकृत अनुभवहीन टीम 16 वर्षों के बाद ओलंपिक फाइनल खेल रही थी.

जफर इकबाल ने बताया था, स्पेन की टीम काफी परिपक्व थी. ग्रेसिया उनका गोलकीपर था. हुआन अमात उनका फुल बैक होता था. वो पेनल्टी कॉर्नर लेने के विशेषज्ञ थे और अपना तीसरा या चौथा ओलंपिक खेल रहे थे. उन्होंने हमारे लेफ्ट फ्लैंक को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था. लेकिन मोहम्मद शाहिद अद्वितीय खिलाड़ी थे. उनका स्टिक वर्क शायद उस समय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था. पहले हाफ में उन्होंने हमें खुलकर खेलने नहीं दिया, लेकिन दूसरे हाफ में शाहिद ने बेहतरीन डॉजिंग कर उनके मैन टू मैन मार्किंग के प्लान को तितर–बितर कर दिया.

पहले दो गोल किए सेंटर फॉरवर्ड सुरिंदर सिंह सोढ़ी ने. स्पेन ने एक गोल उतारा, लेकिन फिर राइट आउट कौशिक ने एक गोल कर भारत को 3–1 से आगे कर दिया.

स्पेन के खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ मैच में झोंका

हाफ टाइम के बाद मोहम्मद शाहिद ने कई खिलाड़ियों को चकमा देते हुए रिवर्स फ्लिक से गोल कर भारत को 4–1 से आगे कर दिया. इस गोल के बाद खेल के परिणाम के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं रह गया.

भारत से आए खेल संवाददाता खेल बीच में ही छोड़ कर प्रेस रूम की तरफ भागे ताकि वहाँ पर उपलब्ध एक–आध अंग्रेजी टाइप राइटरों का पहले इस्तेमाल कर सकें.

इस बीच भारतीय खिलाड़ियों को थोड़ा ध्यान भंग हुआ और स्पेन के खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ मैच में झोंक दिया.

उस टीम के सदस्य मर्विन फर्नांडिस ने बीबीसी को बताया था, स्पेन का कम बैक इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था. उस दिन भास्करन ने टीम को अच्छी तरह संभाला और टीम का मनोबल गिरने नहीं दिया. उन्होंने हमें बार–बार हिदायत दी कि हम अपना धैर्य नहीं खोएँ और अपना स्वाभाविक खेल खेलते रहें.

खतरनाक आखिरी पाँच मिनट

भारत पर स्पेन का दबाव बना ही था कि उसी समय संपूर्ण उत्तर भारत में भूकंप के

जबरदस्त झटके महसूस किए गए. रेडियो पर कमेंट्री सुन रहे लाखों लोग अप. ने–अपने घरों के बाहर भागे. दस मिनट बाद जब वे अपने घरों के अंदर आए, तब तक हुआन अमात पेनल्टी कॉर्नर से भारत पर दो गोल कर चुके थे.

खेल खत्म होने में कुछ मिनट शेष थे. उस समय भी स्कोर भारत के पक्ष में 4–3 था. लेकिन स्पेन के 10 खिलाड़ी भारत के 'डी' में थे.

उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए जफर इकबाल ने बीबीसी को बताया था, खेल खत्म होने में सिर्फ दो या तीन मिनट रह गए थे और स्पेन को शॉर्ट कॉर्नर पर शॉर्ट कॉर्नर मिले जा रहे थे. हाफ लाइन पर खड़े हम जैसे लोग अपने गोल की तरफ देखते ही नहीं थे, इस डर से कि गेंद कहीं गोल के फट्टे पर न लग जाए. आखिरी शॉर्ट कॉर्नर पर भागने की जिम्मेदारी मैंने किसी और को दे दी. हमारे दिल की धड़कनें रुक सी गईं, जब अमात को शॉर्ट कॉर्नर पर रिबाउंड मिल गया. वो गोलकीपर छेत्री से सिर्फ 10 गज की दूरी पर खड़ा हुआ था. उस समय खेल खत्म होने में सिर्फ डेढ़ मिनट बाकी थे. हमारे गोल का बायाँ हिस्सा भी खाली पड़ा था, लेकिन उसका मारा शॉट गोलपोस्ट से चार–पाँच इंच बगल से निकल गया.

16 वर्षों बाद भारत बना ओलंपिक चौंपियन

आखिरी मिनट में स्पेन को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला. दर्शकों ने साँस रोक कर हुआन अमात को एक और शक्तिशाली पेनल्टी कॉर्नर शॉट लेते हुए देखा.

भारतीय गोलकीपर छेत्री मुँदी आँखों से अपनी दाईं ओर झुके और झन्नाटेदार शॉट उनके पैड से लग कर मैदान से बाहर हो गया.तभी फाइनल सीटी बजी और भारत की युवा टीम 16 वर्ष के अंत. राल के बाद ओलंपिक चौंपियन बन गई. भास्करन ने उस मैच को याद करते हुए बीबीसी को बताया था, स्पेन को आखिरी पाँच मिनट में चार पेनल्टी कॉर्नर मिले. उनमें से तीन शॉट मैंने गोल लाइन पर बचाए. ये बहुत ही मुश्किल मैच के बाद मिली जीत थी. इस पूरे टूर्नामेंट के दौ. रान उस समय सोवियत संघ में भारत के राजदूत और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने इंदर कुमार गुजराल भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाने मैदान में मौजूद थे.

इंदिरा गांधी ने दी फोन पर बधाई

फाइनल के बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य अश्वनी कुमार ने विजेताओं को पदक बाँटे. मैच के तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फोन कर भारतीय टीम को बधाई दी. स्पेनिश टीम के जर्मन कोच हॉर्स्ट वेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस जीत से भारत की टीम एक बार फिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हॉकी टीम बन जाएगी.

उस भारतीय टीम के फुल बैक सिल्वानस डुंग डुंग ने उन क्षणों का याद करते हुए बीबीसी को बताया था, जीतने के बाद मैदान में ही चोटी की तीन टीमों को पदक दिए गए. सबसे ऊपर भारत का झंडा देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी आँखों में आँसू आ गए.

शाहिद की दुविधा

भारत लौटने पर विजेता भारतीय हॉकी टीम को लोगों ने अपने सिर आँखों पर बैठाया. इस प्रतियोगिता के बाद से ही मो. हम्मद शाहिद की गिनती दुनिया के सर्व. श्रेष्ठ फॉरवर्ड्स में होने लगी. 19 वर्षीय शाहिद के लिए वो बहुत ही महान क्षण था, जब वह स्वर्ण पदक के साथ अपने पुश्तैनी शहर बनारस पहुँचे.

शाहिद ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, षुझे याद है कि जब 1980 में हम स्वर्ण पदक जीत कर पहले दिल्ली और फिर बनारस पहुँचे, तो स्टेशन पर बहुत से लोग हमें लेने पहुँचे थे. सुबह से लेकर शाम तक हमारे स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किए जाते. मैं जहाँ भी जाता, लोग मुझसे कहते कि आप भाषण दीजिए और मॉस्को के अपने अनुभवों को बताइए. 18–19 साल की उम्र में हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी और मैं सोचता था कि मैं कहाँ फँस गया. मेरे लिए भाषण देने से आसान था भारत के लिए गोल मारना.

Courtesy-www.bbc.com

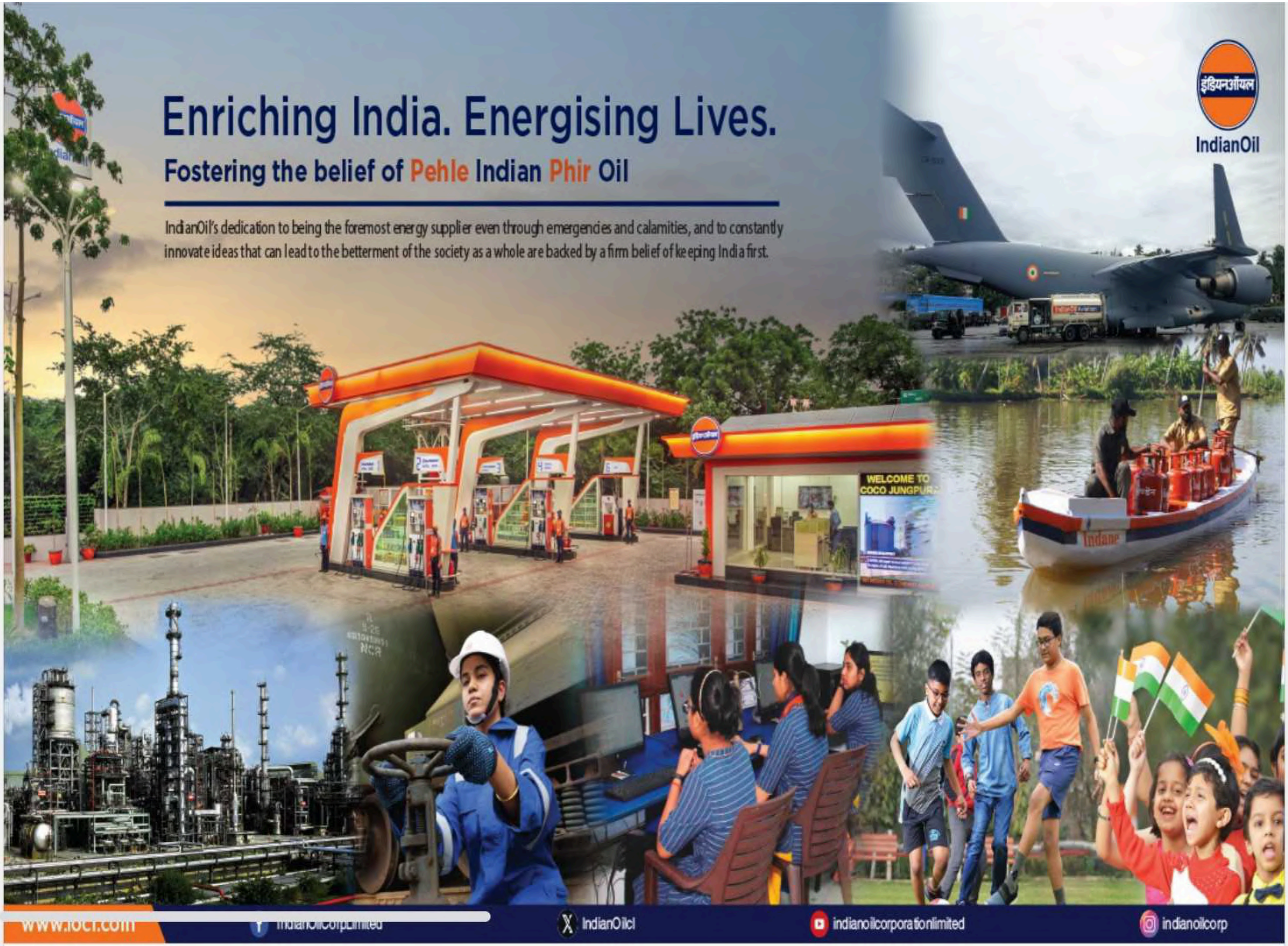

Enriching India. Energising Lives.
Fostering the belief of Pehle Indian Phir Oil
IndianOil's dedication to being the foremost energy supplier even through emergencies and calamities, and to constantly innovate ideas that can lead to the betterment of the society as a whole are backed by a firm belief of keeping India first.
IndianOil
WELCOME TO COCO JUNGPURA
Indane
www.iocl.com
IndianOilcl
indianoilcorporationlimited
indianoilcorp

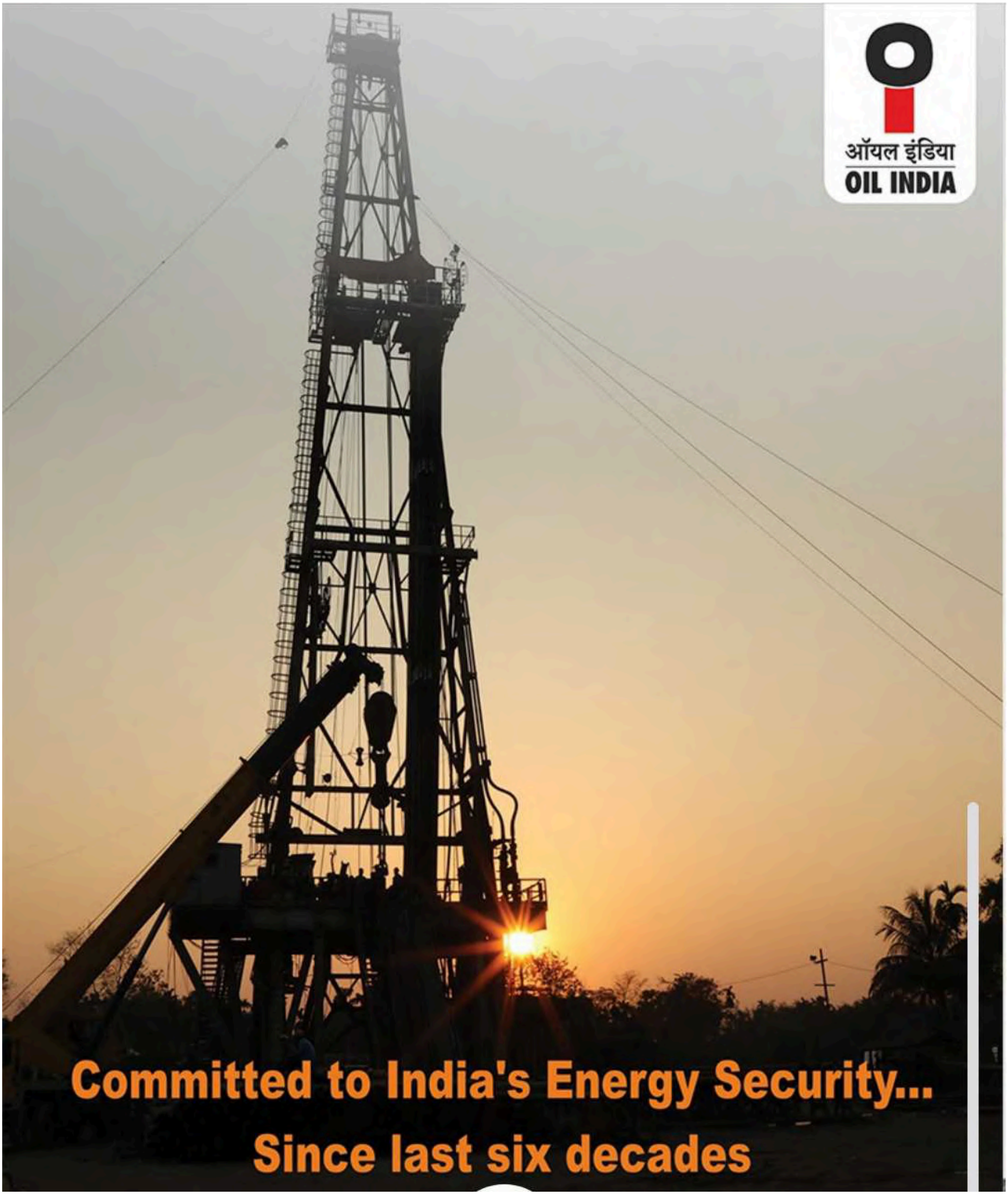
ऑयल इंडिया
OIL INDIA
Committed to India's Energy Security...
Since last six decades